घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 13- शनिवार 14- मार्च 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

संक्षिप्त समाचार

संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आरंभ... बांग्लादेश सरकार से की हिंदुओं के संरक्षण की मांग

समालखा (हरियाणा),13 मार्च 2026। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का शुक्रवार को सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने उद्घाटन किया। इस दौरान सरकार्यवाह की ओर से वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। संघ ने बांग्लादेश सरकार से एक बार फिर आग्रह किया कि वह अपने यहां हिंदुओं के अधिकारों का संरक्षण करे। तीन दिवसीय यह बैठक हरियाणा के समालखा स्थित माधव सृष्टि परिसर में आयोजित की गई है। प्रतिनिधि सभा के प्रारंभ के बाद यहां सह सरकार्यवाह सीआर मुकुंद ने अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर के साथ पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर एवं प्रदीप जोशी सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक के शुरुआती सत्रों में दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों से आए सुधार और मणिपुर में संघ के प्रयासों से आए सकारात्मक परिणामों का स्वागत किया गया। इसके अलावा बांग्लादेश सरकार से एक बार फिर आग्रह किया गया कि हिंदुओं के अधिकारों का वहां संरक्षण प्रदान करे। सीआर मुकुंद ने बताया कि सरकार्यवाह ने अपने प्रतिवेदन में यह जानकारी दी कि संघ के शताब्दी वर्ष में किए गए प्रयासों से 4 हजार स्थान पर 5 हजार से अधिक शाखाओं में वृद्धि हुई है। गृह संपर्क अभियान के तहत संघ के कार्यकर्ता 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचे हैं। तीन लाख से अधिक गांव में संघ के कार्यकर्ता गए हैं। केरल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां संघ के कार्यकर्ता साम्यवादी विचारधारा, मुसलमानों और ईसाई परिवारों से भी मिले हैं।

नंद किशोर यादव ने नगालैंड के राज्यपाल के रूप में ली शपथ...

कोहिमा,13 मार्च 2026। नगालैंड के लोक भवन में शुक्रवार को आयोजित एक समारोह में नंद किशोर यादव ने नगालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। पद की शपथ गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और विधानसभा अध्यक्ष शेरिंगेन लोंगकुमेर की मौजूदगी में दिलाई। यादव को 5 मार्च को राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने अजय कुमार भल्ला की जगह ली, जो मणिपुर के राज्यपाल के तौर पर काम करते हुए नगालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के मंत्री, विधायक, आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि, वरिष्ठ नौकरशाह और पुलिस एवं सुरक्षा बलों के अधिकारी शामिल हुए। समारोह के बाद, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से बातचीत की। अपने संबोधन में, नंद किशोर यादव ने कहा कि भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत में नगालैंड का एक विशेष स्थान है।

एलपीजी संकट पर विपक्ष की नारेबाजी,लोकसभा 16 मार्च तक स्थगित

वित्त मंत्री बोलीं-मुश्किल समय में साथ खड़े हों मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का नोटिस

नई दिल्ली,13 मार्च 2026। लोकसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल की शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने हंगामा किया। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने 8 निलंबित सांसदों की वापसी की मांग की। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा- सदन की मेजों पर चढ़ोगे तो यही एक्शन होगा। संसद की प्रतिष्ठा बनाने की जिम्मेदारी सभी की है। इसके बाद लोकसभा पहले 12 बजे तक और दूसरी बार 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे शुरू हुई कार्यवाही भी केवल 1 घंटा चली। इसके बाद लोकसभा को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले विपक्षी दलों ने संसद परिसर में प्लेकार्ड दिखाकर एलपीजी संकट पर प्रदर्शन किया। राज्य भी 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। सूत्रों के मुताबिक बताया है कि टीएमसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पद से हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में दिया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संकट विदेशों में हो रहे घटनाक्रम के कारण हमारे देश में कुछ मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। सरकार जरूरी फंड मुहैया कराने और पूरी तरह तैयार रहने के लिए कदम उठा रही है। ऐसे समय में विपक्ष को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, लेकिन वह गैर-जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है। संबोधन के दौरान सीतारमण ने बिजनौर के नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण से कहा कि आप अपने नाम के आगे से 'रावण' शब्द हटा लें, इनकी जगह 'विदुर' लगा लें, क्योंकि महाभारत खत्म होने के बाद विदुर बिजनौर आ गए थे।

सीतारमण बोलीं...आर्थिक स्थिरीकरण कोष सरकार को वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 लाख करोड़ का आर्थिक स्थिरीकरण कोष भारत को वित्तीय गुंजाइश देगा, जिससे वह वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सके। उन्होंने कहा कि यह कोष एक 'बफर' (सुरक्षा कवच) के रूप में काम करेगा, जो पश्चिम एशिया जैसी मौजूदा अप्रत्याशित वैश्विक चुनौतियों से पैदा होने वाले झटकों को झेलने में मदद करेगा।

सीतारमण ने कहा...विपक्ष को सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए...

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- विदेशों में हो रहे घटनाक्रमों के कारण हमारे देश के सामने कुछ मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन चुनौतियों का सामना करने, जरूरी फंड मुहैया कराने और पूरी तरह तैयार रहने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे समय में विपक्ष को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए और आम लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए।

इसके बजाय वे ऐसे गैर-ज़िम्मेदाराना कदम उठाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा- पीएम मोदी और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरोसा दिलाया है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

लोकसभा में पारा हुई दूसरी अतिरिक्त अनुदान मांगें 2025-26

लोकसभा ने शुक्रवार को अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगें- 2025-26 के लिए दूसरा बैच को मंजूरी दे दी। इस फैसले के तहत सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति मिल गई है। इसका मतलब है कि पहले से तय बजट के अलावा कुछ नई जरूरी लागतों के लिए पैसा खर्च किया जा सकेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह खर्च बजट 2026-27 में तय राजकोषीय घाटा के लक्ष्य के भीतर ही रहेगा, ताकि वित्तीय अनुशासन बना रहे। सरकार का उद्देश्य है कि अतिरिक्त खर्च देश की जरूरतों और विकास योजनाओं को प्रभावित किए बिना पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से किया जाए।

लोकसभा में पेश हुआ 'ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक, 2026

लोकसभा में 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) संशोधन विधेयक, 2026' पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी जीवन गुणवत्ता सुधारना बताया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम समावेशी और समान अधिकारों वाले समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। विधेयक के जरिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अधिकारों को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।

कांग्रेस ने लागातार असम से झूठ बोला....

किसानों को विदेशों पर निर्भर रखा : पीएम मोदी

गुवाहाटी,13 मार्च 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने असम के लोगों से लगातार झूठ बोला। कांग्रेस की गलत नीतियों ने इस राज्य को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि बाहरी देशों के युद्ध की वजह से हमारे किसानों पर असर पड़ता है। हमने कृषि को बाहरी संकट से बचाने के लिए आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन दिया है। कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वो किसी भी स्थिति देश के लिए ईमानदार नहीं है। मोदी ने कहा कि आज युद्ध की स्थिति में कांग्रेस केवल गलत प्रचार करने में जुटी है। वे केवल देश को अंधेरे में रखना चाहते हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। पीएम ने चाय किसानें के लिए कहा... टी-गार्डन के किसानों का सम्मान करना मेरे लिए कर्ज चुकाने जैसा है। आपकी चाय बेचकर मैं पीएम बन गया। मां कामाख्या देवी ने मुझे चाय बागान के लोगों का कर्ज चुकाने का मौका दिया है। पीएम 13-14 अप्रैल को असम के दो दिन के दौर पर हैं। उन्होंने पहले दिन 24.250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए 3 नई ट्रेनों की शुरुआत भी की। पीएम दो दिन में यहां कुल मिलाकर 47800 रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 14 मार्च को सुबह करीब 10:45 बजे प्रधानमंत्री सिलचर में भूमि पूजन करेंगे और करीब 23,550 करोड़ रुपए के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करेंगे।

पीएम की स्पीच की बड़ी बातें...

- सरकार ने यूपीआई के जरिए किसानों के खातों में सीधे पैसे भेजे। पैसे जमा होने का मैसेज किसानों के मोबाइल पर भी पहुंच गया। दुनिया के कई विकसित देशों में भी इतनी तेज व्यवस्था नहीं है।
- एनडीए सरकार के लिए किसानों का हित सबसे महत्वपूर्ण है। 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के 10 साल में किसानों को करीब 6.5 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के रूप में मिले।
- एनडीए सरकार के समय में किसानों को 20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा एमएसपी मिल चुका है। यूरिया के लिए सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा सब्सिडी दी है ताकि किसानों पर बोझ न पड़े।
- कांग्रेस ने किसानों और रिफाइनरी विकास के लिए ज्यादा काम नहीं किया। आज कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है।
- कांग्रेस झूठे वादों की दुकान है। एक वादे के साथ चार झूठ गिफ्ट में देती है। वहीं, आपके सामने बीजेपी का सफल मॉडल है। 2003 में जब दिल्ली में एनडीए सरकार थी। अटल जी के नेतृत्व में सच्चाई और ईमानदारी से काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं, एलपीजी चिंता का विषय : सरकार

रोजाना 75.7 लाख सिलेंडर बुक हो रहे,ईरान जंग से पहले 55.7 लाख होते थे

नई दिल्ली, 13 मार्च 2026। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किए जाने के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर दबाव बढ़ने के बीच भारत सरकार ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन अवग-अलग मंत्रालयों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार ने कहा कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से एलपीजी हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार ने बताया कि ईरान जंग के कारण देश में गैस बुकिंग की संख्या में लगभग 20 लाख की बढ़ोतरी हुई है। सरकार की तरफ से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी (मार्केटिंग एवं ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने बताया कि जंग से पहले हर रोज औसतन 55.7 लाख सिलेंडरों की बुकिंग होती थी। अभी एक दिन में लगभग 75.7 लाख गैस बुकिंग हो रही है। सरकार ने कहा कि जंग के माहौल के बीच एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। यह लोगों के बीच घबराहट के कारण हो रहा है।

सभी देशों को रूसी तेल खरीदने की इजाजत,अमेरिका ने 30 दिन की छूट दी

नई दिल्ली,13 मार्च 2026। अमेरिका-इजराइल की ईरान से चल रही जंग की वजह से दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर 100 डॉलर के पार चली गई हैं। इसे काबू में करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने दूसरे देशों को भी रूस से तेल खरीदने की अस्थाई मंजूरी दे दी है। रूस के कई ऑयल टैंकर समुद्र में फंसे हैं। इससे पहले अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही थी। हालांकि, इस पर भारतीय अधिकारी कह चुके हैं कि भारत तेल खरीदने के लिए किसी भी देश की इजाजत पर निर्भर नहीं है। वहीं, ईरान चेतावनी दे चुका है कि कच्चे तेल की कीमतें 200 डॉलर के पार पहुंच सकती हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग (वित्त मंत्रालय) ने गुरुवार को एक लाइसेंस जारी किया। इसके तहत उन रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिलीवरी और बिक्री की जा सकती है, जो 12 मार्च की रात 12:01 बजे से पहले जहाजों पर लोड हो चुके थे। यह छूट सिर्फ 11 अप्रैल तक के लिए दी गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि इसका मकसद दुनियाभर में तेल की सप्लाई बढ़ाना है, ताकि बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सके।

वाराणसी स्टेशन पर 3.54 करोड़ का सोना बरामद

दो गिरफ्तार,अफ्रीका से बांग्लादेश होते हुए पहुंचा था भारत

वाराणसी,13 मार्च 2026। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस से जीआरपी थाना के पुलिसकर्मियों ने दो किलो से अधिक सोना बरामद किया है। यह सोना अफ्रीका से बांग्लादेश होते हुए भारत पहुंचा था। इस मामले में जीआरपी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।उनसे पूछताछ की जा रही है। जीआरपी कैंट थाना के निरीक्षक राजोल नागर ने बताया कि महाराष्ट्र के सातार के निवासी बालासो व पूना निवासी तेजस को कैंट रेलवे स्टेशन से जीआरपी पुलिस ने राजधानी एक्सप्रेस से पकड़ा है। यह दोनों शातिर किस्म के हैं और अक्सर इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों युवकों के पास से दो किलो से अधिक सोने के बिस्किट बरामद किये गए। बरामद सोने की कीमत करीब 3.54 करोड़ के करीब बताई जा रही है। इनके पास से बरामद सोना विशेष रूप से अफ्रीकी सोना है।

मोदी साइकोलॉजिकली खत्म...अमेरिका के आगे नरेंदर ने सरेंडर कर दिया,वह अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं : राहुल गांधी

उत्तर प्रदेश,13 मार्च 2026। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा- नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली खत्म हो गए हैं। मोदी अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे, वह अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं और नरेंदर ने सरेंडर कर दिया है। जब मैं यह बात संसद में बोलने जा रहा था तो नरेंद्र मोदी जी भाग कर निकल गए। राहुल गांधी सोमवार को लखनऊ में कांशीराम जयंती पर आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता कर दिया है। क्योंकि अब अमेरिका तय कर रहा है कि हम तेल कहां से लेंगे? एनर्जी सेक्टर के हालात अभी और खराब होंगे। राहुल ने आगे कहा कि कांशीरामजी समाज में बराबरी की बात करते थे। अगर जवाहर लाल नेहरू जी जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते। लेकिन आज भाजपा ने समाज को 15 और 85 बांट दिया गया है। फायदा सिर्फ 15% वालों को मिल रहा है। 50% को अलग-अलग कर दिया गया।

कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग उठाएगी कांग्रेस

कांग्रेस ने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग का प्रस्ताव पास किया है। तय हुआ है कि राहुल गांधी के माध्यम से संसद में यह मांग उठाई जाएगी। यह पहली बार था, जब राहुल गांधी कांशीराम जयंती से 2 दिन पहले कोई बड़ा इवेंट लखनऊ में करने आए थे। कार्यक्रम में करीब 4 हजार लोग शामिल हुए। दलित वोटर्स की सियासत में कांग्रेस का यह बड़ा कदम माना जा रहा है।

राहुल बोले...साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म

राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है। इसे भाजपा वाले नहीं हरा सकते हैं। अगर ये गांधी जी, आंबेडकर जी, ज्योतिबाफुले की पटरी पर चलेगी तो कोई हरा नहीं सकता है। अगर कमी है तो हम में है। हमने मन बना लिया है। कांग्रेस ने मन बना लिया है। जाति जनगणना होगी। गरीब, पिछड़ों आदिवासियों को हिंदुस्तान के पावर सेंटर में जगह मिलेगी। ये कुछ भी कहें मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। मामला आसान हो गया है। इनका आदमी कंप्रोमाइज्ड हो गया है। हमने पकड़ लिया है। साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में मन में पहले हार होती है। फिर होना ही होना है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे दलित भाई, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जिन्होंने प्रेशर बनाया। उन्हें नरेंद्र मोदी को खत्म किया है। मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस गरीब पार्टी है। भाजपा अमीर पार्टी बन गई। नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा धन अडानी को नहीं दिया।

राहुल बोले...कांग्रेस गरीब पार्टी,नेता अमीर हैं...

राहुल ने कहा, कांग्रेस गरीब पार्टी है। कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता अमीर हैं। हम अमीर पार्टी होना ही नहीं चाहते हैं। ये कांग्रेस का डिजाइन गांधी जी के टाइम से यही है। जिस दिन अमीर बन जाएगी, भाजपा बन जाएगी। ये बात मैं इलेक्शन के टाइम समझा। हमारे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। कांग्रेस पर रुकावट नहीं आई। कांग्रेस चलती रही।

गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा,हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कर दी गई है

राहुल गांधी ने कहा,आप मोदी जी का चेहरा तो देखिए। उनके संगठन की पुरानी आदत है। ये पहला उदाहरण नहीं है। इनका लाइन अप है। ये करते जाते हैं। आप देखिए, कल मैंने संसद में एपस्टीन शब्द संसद में बोला। स्पीकर साहब ने कहा नहीं,नहीं नहीं। मैंने कहा कि देखिए। मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला,ये है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है।

ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि भारत पर हमले की वह सोच भी नहीं सकता : राजनाथ सिंह

लखनऊ,13 मार्च 2026। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया गया कि वह फिर कभी उबर भी नहीं पाएगा। भारत की सेना पूरी तरह से सतर्क और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लखनऊ में दूसरे चरण के ग्रीन कॉरिडोर का लोकार्पण और तीसरे व चौथे चरण के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। गोमती नदी के तट पर झूलेलाल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ का तेजी से विकास हो रहा है और डिफेंस सेक्टर में भी लखनऊ पीछे नहीं है। यहां ब्रह्मोस मिसाइल,एयरो स्पेस से संबंधित काम भी हो रहा है और यह शहर देश की सुरक्षा व्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ आपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया गया कि वे दोबारा ऐसी हरकत करने की सोच भी नहीं सकते हैं। अगर सोचा तो वे इस बार के हमले से कभी उबर भी नहीं पायेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले हर मंसूबे को करारा जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि लोग मुख्यमंत्री योगी को बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। इन्होंने माफियाओं को सही कर दिया, लेकिन बुलडोजर सिर्फ तोड़ने का ही नहीं बल्कि विकास की नयी जमीन भी तैयार करता है। उन्होंने घोषणा की कि आने वाले कुछ ही दिनों में लखनऊ से कानपुर की यात्रा महज 35 से 45 मिनट में पूरी हो सकेगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे निवेश का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान की यात्रा पर जा सकेंगे।

संपादकीय

मृत्यु में गरिमा

किसी भी समाज में यह प्रबल धारणा रही है कि परिवार के किसी सदस्य की तब तक सेवा की जाए, जब तक उसके प्राण कुदरती तौर पर न निकल जाएं। खासकर भारतीय समाज में इस मुद्दे को लेकर गहरी संवेदनशीलता रही है। कई स्थानों पर तो अपने आत्मीय की मृत्यु के बाद भी उसे वर्षों तक जीवन लौटने की आस में घर पर रखा गया। लेकिन जब कोई अपना प्रिय उस स्थिति में पहुंच जाए, जहां से सामान्य जीवन में लौट पाना संभव ही न हो,तो बदलते वक्त के साथ कानून के दायरे में उसकी मुक्ति की भी बात होने लगी है। हाल ही में देश के सुप्रीम कोर्ट का 13 वर्ष से कोमा में रहने वाले एक युवा के लिये निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देने का निर्णय, जीवन के अंतिम चरण की देखभाल पर भारत में विकसित होते न्यायशास्त्र में नया मोड़ है। किसी असाध्य स्थिति में कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति देने वाला यह फैसला, अदालत द्वारा पहले से निर्धारित प्रक्रिया का पहला व्यावहारिक प्रयोग है। निस्संदेह,यह मामला उन रोगियों के परिवारों के सामने उपस्थित पीड़ादायक दुविधा को ही उजागर करता है, जिनके ठीक होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं होती। जो महज चिकित्सकीय मदद से ही जीवित रहते हैं। इस मामले में चिकित्सा बोर्डों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि निरंतर उपचार का कोई चिकित्सीय उद्देश्य नहीं था। इससे केवल जैविक अस्तित्व को ही लंबा खींच दिया गया। बहरहाल,इस बाबत अदालत की स्वीकृति एक कठिन सत्य को स्वीकार करती है कि जीवन की गरिमा, मृत्यु में भी गरिमा तक विस्तारित होनी चाहिए। निस्संदेह, भारत में इच्छामृत्यु पर कानूनी प्रगति धीमी रही है। इस मामले में पहली बार अरुणा शानबाग मामले में ध्यान दिया गया था। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के अंतर्गत गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार देने के साथ यह मुद्दा अपने चरम पर पहुंचा। दरअसल, इच्छामृत्यु से जुड़ी दुविधा, इससे जुड़े सिद्धांतों के क्रियान्वयन की अनिश्चितता को लेकर बनी रही है।

जिसके चलते परिवारों व डॉक्टरों को जटिल प्रकिया व कानूनी चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। निस्संदेह, हालिया फैसले से भी न्यायिक दिशा-निर्देशों मात्र पर निर्भर रहने की सीमाएं उजागर हुई हैं। बल्कि यहां तक कि देश की शीर्ष अदालत ने भी निष्क्रिय इच्छामृत्यु,लिविंग विल और जीवन को लेकर अंतिम निर्णय को नियंत्रित करने वाले व्यापक कानून की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। निस्संदेह,ऐसे कानून में नैतिक संवेदनशीलता और प्रक्रियात्मक स्पष्टता के बीच बेहद संतुलन होना चाहिए। यह प्रक्रिया कमजोर रोगियों को दुर्व्यवहार से बचाते हुए, यह भी सुनिश्चित करे कि परिवार और चिकित्सा पेशेवर कानूनी परिणामों के भय के बिना कार्य कर सकें। इस मामले में स्पष्ट प्रोटोकॉल, पारदर्शी चिकित्सा मूल्यांकन और रोगी की स्वायत्तता का सम्मान आवश्यक है। अंतत, निष्कर्ष यह भी है कि जब उपचार असंभव हो तो चिकित्सा उपायों से रोगी की पीड़ा को लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। निःसंदेह, शीर्ष अदालत की कारगर सलाह के मद्देनजर देश के नीति-नियंताओं को एक मानवीय कानूनी ढांचा तैयार करने के बारे में गंभीरता से सोचना चहिए। जो टाली न जा सकने वाली विषम स्थिति में व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने व मरने की अनुमति दे सके। निस्संदेह,देश में इस बाबत एक संवेदनशील कानून बनाने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। साथ ही ऐसा कानून बनाते वक्त मानवीय संवेदनशीलता तथा कानूनी सुरक्षा कवच के बीच संतुलन बनाना भी उतना ही जरूरी होगा। वहीं हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा संकीर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के लिये किसी व्यक्ति की दबाव में इच्छामृत्यु के लिये परिस्थितियां पैदा न की जा सकें। दुनिया के तमाम विकसित देशों में इस आशंका के चलते ही इच्छमुत्यु को कानूनी रूप देने से परहेज किया गया है। यह जटिल मामला भी है। जिसके निर्धारण के लिये कानूनी स्पष्टता और मामले की गहन निगरानी भी उतनी ही जरूरी है।

मासिक धर्म अवकाश पर संतुलित दृष्टिकोण जरूरी!

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम.मप्र.

महोदय, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महिला छात्रों और कर्मचारियों के लिए देशव्यापी मासिक धर्म अवकाश (पीरियड्स लीव) की नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि यदि इस प्रकार की अनिवार्य व्यवस्था बनाई जाती है तो निजी कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से हिचक सकती हैं। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि संबंधित विभाग और प्राधिकारी सभी हितधारकों से चर्चा करके इस विषय पर नीति बनाने की संभावना पर विचार कर सकते हैं। यह विषय संवेदनशील होने के साथ-साथ व्यावहारिक पहलुओं से भी जुड़ा है। महिलाओं को पहले से ही मातृत्व के लिए लगभग छह माह का अवकाश मिलता है, जो कि Maternity Benefit Act, 2017 के तहत बढ़ाया गया है। ऐसे में यदि हर महीने अतिरिक्त चार दिन का अनिवार्य अवकाश लागू किया जाए तो कई निजी संस्थानों और कंपनियों पर इसका आर्थिक और प्रबंधकीय दबाव पड़ सकता है। इस कारण यह आशंका भी व्यक्त की जाती है कि कुछ नियोक्ता महिलाओं की भर्ती से बचने की कोशिश कर सकते हैं, जो लैंगिक समानता के लक्ष्य के विपरीत होगा। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि मासिक धर्म महिलाओं की स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है। कुछ महिलाओं को इस दौरान अत्यधिक दर्द और शारीरिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए कार्यस्थलों और शिक्षण संस्थानों में संवेदनशील वातावरण, लचीले कार्य समय, स्वच्छ शौचालय और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना भी उतना ही आवश्यक है। आज चिकित्सा और स्वच्छता के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। बेहतर सैनिटरी उत्पादों और जागरूकता के कारण अधिकांश महिलाएं इस दौरान भी सामान्य जीवन और कार्य को सुचारू रूप से जारी रखती हैं। पिछले कई दशकों से महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, उद्योग और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करती रही हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस विषय पर भावनात्मक नहीं बल्कि संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। यदि किसी संस्था या राज्य सरकार को लगता है कि वहां ऐसी व्यवस्था संभव है तो वह स्थानीय स्तर पर लचीली नीति बना सकती है। लेकिन देशभर में एक समान अनिवार्य नीति लागू करने से पहले इसके सामाजिक, आर्थिक और रोजगार संबंधी प्रभावों का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। अंततः लक्ष्य यही होना चाहिए कि महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर, तीनों के बीच संतुलन बना रहे। तभी वास्तविक अर्थों में समानता और संवेदनशीलता का वातावरण तैयार हो सकेगा।

धान का कटोरा या अफीम का गमला?
छत्तीसगढ़ में 'नई फसल' का रहस्य

धान का कटोरा या अफीम का बगीचा? छत्तीसगढ़ की खेती ने बदला 'फसल चक्र'

- खेतों में अफीम लहलहाई, जिम्मेदार बोले-हमें तो बस हरियाली दिखी
- अफीम उगती रही, पहरेदार सोते रहे...अब जागी व्यवस्था की नींद
- किसानों ने बोया अफीम, सिस्टम ने बोया सन्नाटा
- अफीम की फसल पकड़ी गई,जिम्मेदारी अब भी कच्ची

अफीम की खेती पर खुलती परतें, जिम्मेदारों की आंखों पर अब भी परदा

फसल खेत में उग रही थी, खबर विधानसभा में उगी

अफीम के पौधे बोले - हम तो महीनों से खड़े थे, अब सबको कैसे दिखे?

छत्तीसगढ़ को वर्षों से 'धान का कटोरा' कहा जाता रहा है,किसान मेहनत करते हैं,सरकार समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और खेतों में धान लहलहाता है, लेकिन हाल के दिनों में जो खबरें सामने आई हैं,उनसे लगता है कि राज्य की कृषि व्यवस्था शायद चुपचाप एक नई फसल का स्वागत कर रही थी,वह है अफीम। पहले दुर्ग में खबर आई कि वहां अफीम की खेती पकड़ी गई, लोगों ने सोचा, चलिए कोई इकलौता मामला होगा, किसी किसान ने शायद गूगल देखकर नई खेती का प्रयोग कर लिया होगा,लेकिन कुछ ही दिन बाद बलरामपुर से भी खबर आ गई कि वहां भी खेतों में अफीम लहरा रही थी,अब हाल यह है कि खबरें जिस रफ्तार से सामने आ रही हैं, ऐसा लगने लगा है कि धान,गेहूं और मक्का के बीच कहीं 'अफीम' भी चुपचाप फसल चक्र का हिस्सा बन गई थी।

ओंकार पाण्डेय सूरजपुर,छत्तीसगढ़

खेतों में अफीम, पर जिम्मेदारों की आंखों में नींद

सबसे दिलचस्प बात यह है कि अफीम की खेती इतनी मात्रा में हो रही थी,लेकिन जिनकी जिम्मेदारी निगरानी की थी,उन्हें शायद इसकी भनक भी नहीं लगी,अब यह तो तय है कि अफीम कोई तुलसी का पौधा नहीं है जो घर के कोने में उग जाए और किसी को पता ही न चले। यह खेती खेत में होती है, पौधे उगते हैं, फूल आते हैं और फिर उससे रस निकाला जाता है,लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदनशीलता देखिए –खेत में अफीम उग रही थी और तंत्र को शायद सिर्फ हरियाली दिखाई दे रही थी।

जिम्मेदार विभागः सबको नहीं पता,लेकिन सबको पता

राज्य में पुलिस है, आबकारी विभाग है,नारकोटिक से जुड़े तंत्र हैं और स्थानीय प्रशासन भी है, यानि व्यवस्था इतनी मजबूत है कि यदि कोई किसान अपने खेत में एक झोपड़ी भी बना ले तो नोटिस पहुंच जाता है,लेकिन अफीम की खेती...? वह शायद इतनी 'संस्कारी' फसल निकली कि किसी विभाग को परेशान ही नहीं करना चाहती थी,अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यह खेती किसके संरक्षण में हो रही थी? पुलिस के आशीर्वाद से? आबकारी विभाग की कृपा से? या फिर नारकोटिक विभाग की 'दूरदर्शी निगरानी' में? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सबको लगा हो कि यह जिम्मेदारी किसी और की है, और इसी भरोसे अफीम खेतों में फलती-फूलती रही।

लाइसेंस कागजों में था या कल्पना में?

अफीम की खेती भारत में पूरी तरह अवैध नहीं है, लेकिन इसके लिए सख्त लाइसेंस चाहिए,अब दिलचस्प सवाल यह है कि क्या इन खेतों में लाइसेंस भी था? अगर था तो शायद वह कागजों में कहीं घूम रहा होगा, और अगर नहीं था तो शायद यह खेती मौखिक अनुमति के भरोसे चल रही थी, हमारे यहां मौखिक आदेशों की परंपरा भी बड़ी मजबूत रही है –कागज बाद में आते हैं, काम पहले हो जाता है।

विधानसभा में शोर, खेतों में सन्नाटा

अब मामला विधानसभा तक पहुंच चुका है। सदन में हंगामा हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं और जवाब तलाशे जा रहे हैं,लेकिन खेतों में खड़े अफीम के पौधे शायद यह सोच रहे होंगे कि 'हम तो महीनों से यहां खड़े थे,अब अचानक सबको हमारी याद कैसे आ गई?' असल सवाल अभी भी बाकी सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है,यह खेती कितने सालों से हो रही थी? क्या यह पहली बार पकड़ी गई है, या यह कई वर्षों से चल रही कहानी का सिर्फ पहला खुला पन्ना है? और यदि यह सालों से हो रही थी, तो क्या जिन घरों में पहले यह खेती हुई, वहां अब भी अफीम का भंडार छिपा हो सकता है?

अंत में...

छत्तीसगढ़ के खेत मेहनत और ईमानदारी की पहचान रहे हैं, लेकिन यदि इन्हीं खेतों में अवैध फसलें उगने लगें और जिम्मेदार तंत्र को उसकी खबर ही न हो,तो यह केवल कानून का सवाल नहीं रह जाता, यह व्यवस्था की नींद का भी सवाल बन जाता है, अब जब अफीम की फसल पकड़ी जा रही है, तो उम्मीद है कि जांच की दरांती सिर्फ खेतों तक ही नहीं रुकेगी,बल्कि उन जिम्मेदारियों तक भी पहुंचेगी जिनकी निगरानी में यह 'नई खेती' इतनी आराम से फलती-फूलती रही,कहीं ऐसा न हो कि अंत में यह निष्कर्ष निकले की अफीम खेतों में कम, व्यवस्था की बेफिक्री में ज्यादा उगी थी।

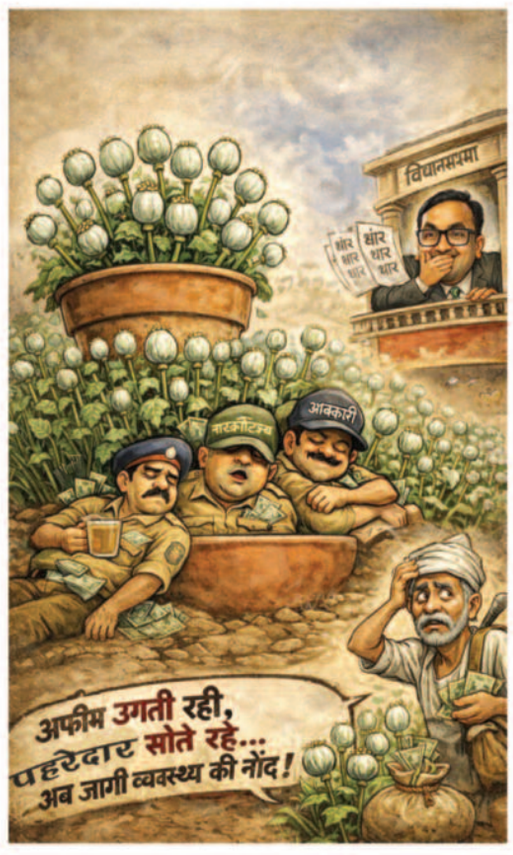

ईश्वर' शब्द के शासक से शिव होने की यात्रा!

ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है? ईश्वर सत्य है, अपने इस विचार को महात्मा गांधी ने वर्ष 1929 में पलटकर सत्य ही ईश्वर है, करते हुये तर्क दिया कि जब उन्होंने ईश्वर सत्य है का अनुभव किया तब सत्य ही ईश्वर की ओर कदम बढ़ाने का मार्ग बना,यानि सत्य को ईश्वर माना। देश उस समय महात्मा गांधी से प्रभावित था, इसी कड़ी में राजकपुर ने वर्ष 1978 में एक फिल्म-सत्यम शिवम सुन्दरम बनाई जिसका शाब्दिक अर्थ सच्चा,कल्याणप्रद,और मनोहर बताया ओर इस फिल्म में पंडित नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखा ओर लतामंगेशकर के सुर में पिरोया गीत ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है',कि रिकार्डिंग तत्समय रेडियो स्टेशनों सहित हर गाँव शहर के मंदिरों में गूँजती ओर सभी के दिलों के तारों को छेड़ती रही। उस समय यह मानसिकता सभी में बलवती होती गई कि ईश्वर कोई ओर नहीं परमात्मा शिव ही ईश्वर है।

आत्माराम यादव नर्मदापुरम,मध्यप्रदेश

हमारे चार वेद है जिसमें सभी देवताओं की सत्ता का विस्तृत वर्णन है ओर किसी भी देवता को ईश्वर की संज्ञा नही दी गई है। किन्तु कुछ ऋषि मुनिओं का कहना है कि- ईश्वर ने मनुष्यो को जहां/जगत बनाया अपितु ईश्वर की रचना मनुष्यों ने की है।' यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाये तो ईश्वर का वर्तमान स्वरूप किसी भी देवालय,मंदिर मठ आदि में देखे तो वह परिवर्तित और परिवर्धितरूप है। क्योंकि प्राचीन भारतीय साहित्य मे वर्तमान ईश्वर के लिय कोई स्थान नहीं है। ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम वेद है उसमें कही भी एक बार भी ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है ओर ठीक ऐसा ही सामवेद और यजुर्वेद है, जिसमें ईश्वर का उल्लेख नही किया गया है। अथर्ववेद में ईश्वर शब्द का प्रयोग देवताओं के लिए नहीं किया जाकर केवल साधारण स्वामी, राजा आदि के अर्थ मे ही इसका उपयोग हुआ है। अतः वैदिक देवता ईश्वर नहीं है तो ईश्वर कौन है इसकी भूमिका में कुछ लिखने कि प्रेरणा बलवती हुई है ओर अपना ज्ञानोदय हेतु वेदों सहित अन्य ग्रन्थों के महासमुन्द्र कि लहरों से आप्लावित होने का अवसर मिला है।

वेदों मे अग्नि ओर पृथ्वी को स्थानीय देवता वायु ओर इन्द्र अन्तरिक्ष तथा सूर्य को धुलोक देवता कहा गया है ओर उनकी अनेक विभूतिओ ओर कर्मों के मान से उनके अनेक नाम कहे गए है। कुछ विद्वानों का कथन है कि वेदों में ईश्वर शब्द के न होने से क्या है,उनमें सृष्टि-कर्ता ईश्वर का अग्नि, प्रजापति, पुरुष. हिरण्यगर्भ आदि शब्दों द्वारा वर्णन तो प्राप्त होता है। वही कुछ का मानना है कि वेदों में एक ईश्वर का नहीं अपितु अनेक देवताओं का विधान है। वैदिक देवता इन्द्र, अग्नि, वरुण, मित्र, पूषा आदि सब कार्मिक देवता हैं। दूसरे शब्दो में वे 'नियतकर्माणः' या 'विभज्य-कर्मकारिणः' अर्थात् अपने अपने नियत कर्मों को करने वाले हैं। इन में से किसी एक को हम वास्तव में 'देवोंका देव' या 'देवाधिदेव' नहीं कह सकते। तथा वैदिक देवों में से एक भी देव ऐसा नहीं है जिसको वर्तमान में ईश्वर का स्थान दिया जा सके। क्योंकि वैदिक देवता नियतकर्मा हैं. तथा उनकी उत्पत्ति का एवं उनके शरीरों का उल्लेख वेदों में ही उपलब्ध होता है। यह सब होते हुए भी आधुनिक विद्वानों ने वेदिक देवताओं का अर्थ ईश्वर परक करने का प्रयत्न किया है। देखा जाये तो वेदों में ही 'प्रजापति' जैसे देवता हैं जो आपाततः बहुत कुछ परमेश्वर के स्थानीय प्रतीत होते है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रजापति को भी हम देवाधिदेव नही कह सकते क्योंकि वह भी अनेक देवताओं में से कंवल एक देवता है। इस लिए यही प्रतीत होता है कि वैदिक समय में, उपनिषदों को यदि शामिल कर लें तो भी,सर्व-साधारण का काम उपर्युक्त कार्मिक या नियत-कर्म देवताओं से ही चल जाता था। उन को किसी देवाधिदेव या परमेश्वर की उपासना की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती थी। दूसरी ओर, तत्त्वज्ञानियों की तृप्ति केवल उन देवताओं से नहीं हो सकतो थी। वे भेद में अभेद और अनेक में ऐक्य देखना चाहते थे। इस लिए उनका काम ब्रह्म से चलता था । आज कल का हिंदू-धर्म निगमागम-धर्म का संमिश्रण समझा जाता है। निगम का अर्थ वेद, और आगम का अर्थ तंत्र लिया जाता है। इस लिए दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आज कल के हिदू-धर्म का आधार वैदिक और तान्त्रिक धर्मों के संमिश्रण पर है। आधुनिक हिंदू-धर्म में प्रचलित देव-ताओं और दैनिक तथा विशिष्ट नैमित्तिक कर्मकांड के देखने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि वह केवल शुद्ध वैदिक धर्म से बहुत भिन्न है। पर इस का अर्थ यह नहीं है कि तांत्रिक धर्म वैदिक धर्म से नवान है। विद्वानों का ख्याल है कि तांत्रिक धर्म, कम से कम भारतवर्ष में तो, वैदिक धर्म से प्राचीन ही है। दूसरी ओर यही बात प्रचलित रही है कि ईश्वर ने मनुष्यो को बनाया किन्तु किस ईश्वर ने मनुष्य ओर उसके संसार कि रचना की, यह गंभीर चिंतन का विषय बनने से इसका उत्तर खोजा जाना आवश्यक हो गया है ? ऋग्वेद जो कि संसार का प्राचीनतम साक्षी ग्रंथ है उसमे एक बार भी ईश्वर शब्द का हो प्रयोग नहीं किया गया है, यही स्थिति सामवेद और यजुर्वेद की है। इनसे हटकर अथर्ववेद में अवश्य ही 'ईश्वर' शब्द? के दर्शन होते हैं, परन्तु वहाँ भी केवल साधारण (स्वामी) अर्थ मे ही इसका प्रयोग देवी देवताओं के लिए हुआ है। अतएव यह आवश्यक है कि वैदिक देवों का यथार्थ स्वरूप समझ लिया जाय । संस्कृत साहित्य में अभी तक हमें ऐसा दूसरा शब्द नहीं मिला जिस का इतिहास 'ईश्वर' शब्द के इतिहास के समान रोचक तथा महत्वपूर्ण माना जा सके। 'ईश्वर' शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य मे, मोटे तौर पर, दो विभिन्न अर्थों में पाया जाता है। साधारणतया तो 'ईश्वर' शब्द का अर्थ 'जगन्नियंता, सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापक, देवाधिदेव प्रभु' ही देखा जाता है। आज कल के सर्व साधारण के व्यवहार में 'शिव,' 'विष्णु,' 'राम,' 'कृष्ण' आदि शब्दों को छोड़ कर, जो परमेश्वर के अर्थ को प्रकट करने के साथ ही संप्रदाय-वाद को भी प्रकट करते हैं, इन शब्दों का संबंध विभिन्न शैव,वैष्णव आदि संप्रदायों से ही है, जो शब्द सांप्रदायिक भाव के बिना उस परमप्रभु के लिए प्रयुक्त होते है उनमें ईश्वर,परमेश्वर ही प्रमुख है। इस सर्वसाधारण को छोडकर संस्कृत साहित्य में ईश्वर शब्द का प्रयोग अधिकतर ऊपर के ही अर्थ में पाया जाता है। पाणिनी,अष्टाध्यायी ओर पतांजल महाभाष्य में ईश्वर शब्द अनेक बार प्रयोग में आया है जिसमे उसका अर्थ ईश्वर या परमात्मा के लिए नहीं किया गया है बल्कि छोटे अर्थों में उसका भाव राजा या शासक के रूप में उपयोग किया गया है। देखा जाये तो ऋषि-मुनि महात्माओं में जो अलौकिक शक्तियाँ होती हैं उन को कोई 'ऐश्वर्य' शब्द से निर्देश नहीं करता, किन्तु रिद्धी 'सिद्धि,' 'शक्ति' जैसे शब्दों का हो प्रयोग उनके लिए किया जाता है। इस से स्पष्ट है कि 'ऐश्वर्य' शब्द लौकिक वैभवशाली 'राजा' या 'शासक' के अर्थ को रखने वाले 'ईश्वर' शब्द से निकला है, न कि 'परमेश्वर' के अर्थ को रखने बाले 'ईश्वर' शब्द से। जैसा कि सभी जानते है कि योग-संबंधी या आत्मिक सिद्धियों या शक्तियों के लिए 'ऐश्वर्य' शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह 'ऐश्वर्य' शब्द बड़ा प्राचीन है। इसलिये 'ईश्वर' शब्द के जिस अर्थ को लेकर यह निकला है वह अर्थ भी अति प्राचीन ही होना चाहिए,इसी से प्रेरित हो कर हमने प्राचीनतम वैदिक साहित्य से ले कर संस्कृत ग्रंथों को देखना शुरू किया ओर हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि 'ईश्वर' शब्द का प्रयोग 'परमेश्वर' के अर्थ में बहुत पीछे से होने लगा है। इस के कारण का विचार भी हम अर्थ या भाव की दृष्टि से नीचे वैदिक संहिताओं का दिग्दर्शन से शुरुआत करते है। ऋग्वेदसंहिता में 'ईश्वर' शब्द एक बार भी प्रयोग नही हुआ है। हाँ, यह शब्द जिस धातु ईश-से बना है उस का प्रयोग, क्रिया रूप से, अनेक स्थलो में आता है जिसमें 'ईश्वर' शब्द की तरह ही 'ईश' धातु से निकला है और इस प्रकार 'ईश्वर' का स्थानीय तथा संबंधी है, 'ईशान' है। इस का अर्थ भी ऋग्वेद में सामान्य रूप से 'समर्थ' है, और यह इंद्र आदि देवताओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे-ईशानो थवया वधम् (201/5/10) अर्थात्, हे इंद्र-देव । तुम समर्थ हो। तुम हनन को हम से दूर रक्खो। 'ईश' धातु का प्रयोग उक्त अर्थ में ही दूसरी संहि?ताओं में भी आता है। इस लिए इस का उल्लेख हम आगे नहीं करेंगे। 'ईशान' शब्दै के अर्थ मे दूसरी संहिताओं में धीरे धीरे कुछ भेद होता गया है। यजुर्वेद और अथर्ववेद में इस का प्रयोग अग्नि-देवता के लिये विशेषण रूप से हुआ है, पर अधिक प्रयोग शिव या रुद्र के लिए ही है। यह प्रवृत्ति चढ़ती गई और अंत में यह 'शिव' का वाचक एक रूढ़ शब्द बन गया। इस शब्द का भी उल्लेख हम आगे प्रायः नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लेख का मुख्य विषय 'ईश्वर' शब्द ही है और वहाँ यहाँ के 'ईश्वरः' के स्थान में 'ईशानः' पाठ है। इसी से स्पष्ट है कि यहाँ भी 'ईश्वर' का अर्थ सामान्यरूप से स्वामी या समर्थ ही है और अभी तक गढ़ अर्थ परमेश्वर का नहीं है। (5) कालो ह सर्वस्वेश्वरो यः पितासीत् प्रजापतेः । (भय0 19153/8)। यहाँ भी काल को 'सब का स्वामी' कहा है।

मोनिका झगा

इच्छा मृत्यु

'आनंद' भरे जीवन में आई एक बेहद काली शाम,
बस बन कर रह गया जीवन जन्म-मृत्यु का संग्राम,
रक्षाबंधन का वो दिन था बहन ने दी भाई को बधाई,
विधाता के लेख से कुछ घंटों बाद घायल हुआ भाई।

एक पल में सपनों का संसार शीशे की तरह हुआ चूर,
कोमा में हरीश आया और असहाय दर्द बना नासूर,
अब जागेगा लाल मेरा माँ का मन हर बार ये कहता,
बाप का दिल जवान बेटे को मौन देख-देख बस रोता।

छोटे भाई ने खोया सिर पर बड़े भाई का आशीष हाथ,
बहन की आँखों में थमते नहीं आंसू कैसा संकट नाथ,
13 वर्षों तक की तपस्या दिन-रात करी सबने सेवा,
बेहतरीन इलाज करवाया कमी नहीं कोई सुरक्षा दवा।

दिन पर दिन यह दुःख होता गया और अधिक गहरा,
हुई नहीं हरीश में कोई हलचल बढ़ता गया बस अंधेरा,
आखिर अंत में सुप्रीम कोर्ट से परिवार ने की गुहार,
इच्छा मृत्यु दे दो तड़प रहा है मेरा बेटा होकर लाचार।

सुप्रीम कोर्ट ने दुःखी मन से इस केस पर हाँ करी,
इच्छा मृत्यु हरीश को शायद देना चाहते है श्री हरी,
बुझे मन से माँ ने कहा सुकून की नींद सो जाना लाल,
माफ़ी माँग रही हूँ बेटा रख नहीं सकी मैं तेरा ख्याल।

(हरीश राणा का केस और सुप्रीम कोर्ट की हाँ)

सुविचार

इन्सान तब तक
सहन करता है जब तक
उसकी सहन करने की क्षमता होती है,
उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरुरी
समझता है और ना तो अपनों को !!

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटाराअम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

C M Y K

अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर दो नए प्लेटफॉर्म बनेंगे,फुट ओवर ब्रिज का काम भी जल्द शुरू

सांसद चिंतामणि महाराज के प्रयासों से 10 करोड़ से अधिक की लागत से हो रहा विकास,रायपुर के लिए सीधी इंटरसिटी ट्रेन का प्रस्ताव भी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के विस्तार और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण विकास कार्य शुरू किए जा रहे हैं। स्टेशन में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 और 3 के निर्माण के साथ नई लूप लाइन बनाई जाएगी, वहीं फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का निर्माण भी जल्द प्रारंभ होगा। रेलवे के एईएन अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि अंबिकापुर स्टेशन में नए प्लेटफॉर्म का निर्माण सांसद के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की लंबाई भी लगभग 80 मीटर तक बढ़ाई जा रही है, जिससे लंबी ट्रेनों के संचालन में सुविधा होगी। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल सिंह मेजर ने कहा कि अंबिकापुर में नए प्लेटफॉर्म का निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। सांसद की सक्रियता के कारण स्टेशन का लगातार विकास हो रहा है। स्टेशन के सौंदर्यीकरण के बाद नए प्लेटफॉर्म बनने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।

रायपुर के लिए इंटरसिटी ट्रेन का प्रस्ताव : सदस्य मुकेश तिवारी ने बताया कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में वाशिंग पिट का

कार्य अंतिम चरण में है और इस वर्ष के अंत तक नए प्लेटफॉर्म का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अंबिकापुर से नई ट्रेनों के संचालन का रास्ता आसान होगा। उन्होंने बताया कि अंबिकापुर से रायपुर के लिए सीधी इंटरसिटी ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेलवे के पास भेजा गया है। प्रस्ताव के अनुसार ट्रेन सुबह 4 बजे अंबिकापुर से रवाना होकर सुबह 11 बजे रायपुर पहुंचेगी और शाम 4 बजे रायपुर से चलकर रात 11 बजे अंबिकापुर पहुंचेगी।

दोहरीकरण और पार्किंग समस्या पर भी चर्चा : मुकेश तिवारी ने कहा कि अंबिकापुर से सूरजपुर रोड के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण क्षेत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके अलावा स्टेशन में पार्किंग की समस्या को दूर करने और स्टेशन तक अलग पहुंच मार्ग बनाने की संभावनाओं पर भी रेलवे विचार कर रहा है। स्टेशन के दूसरे छोर से ऑटो की निकासी के लिए अलग मार्ग बनाए जाने से जाम की समस्या कम होगी।

सांसद ने जताया आभार

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से प्लेटफॉर्म और फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, वहीं पुराने प्लेटफॉर्म की लंबाई भी बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित स्टेशन का लोकार्पण किया गया था। सांसद ने रेलवे के विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर के विकास के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा और समय-समय पर सुझाव भी देते रहना चाहिए। इस दौरान सांसद ने अनिल सिंह मेजर, करताराम गुप्ता, कैलाश मिश्रा और मुकेश तिवारी के योगदान की सराहना की। साथ ही रेलवे अधिकारियों को निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश भी दिए।

घरेलू सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से आज अपर कलेक्टर श्री सुनील कुमार नायक की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की सभी 17 गैस एजेंसियों के संचालकों को उपभोक्ताओं को समय पर और व्यवस्थित रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

बुकिंग के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा : बैठक के दौरान गैस एजेंसी संचालकों ने जानकारी दी कि नई सॉफ्टवेयर व्यवस्था के अनुसार अब उपभोक्ता एक निश्चित अंतराल के बाद ही अगली रिफिल बुक कर सकेंगे। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता अपनी पिछली रिफिल प्राप्ति के 45 दिन बाद ही अगली बुकिंग कर पाएंगे, जबकि शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए यह समय-सीमा 25 दिन निर्धारित की गई है। अपर कलेक्टर श्री नायक ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि से पहले की गई कोई भी बुकिंग सॉफ्टवेयर द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे इस समय-सीमा का पालन करते हुए ही अपनी अगली रिफिल की ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग कराएं,ताकि वितरण व्यवस्था सुचारू बनी रहे और सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सके।

अवैध उपयोग पर रहेगी कड़ी नजर : अपर कलेक्टर श्री नायक ने घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर संबंधित अधिकारियों और गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि इस प्रकार की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए। यदि कहीं भी घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया जाता है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पारदर्शिता और स्टॉक प्रबंधन के निर्देश : बैठक में पारदर्शिता और बेहतर स्टॉक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। सभी गैस वितरक एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने कार्यालय परिसर के बाहर गैस सिलेंडर के उपलब्ध स्टॉक तथा वर्तमान रिफिल दर का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन करें, ताकि उपभोक्ताओं को सही और अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके। इसके साथ ही एजेंसी संचालकों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि ऑयल कंपनियों से गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि समय पर प्रेषित की जाए, जिससे किसी भी स्थिति में स्टॉक की कमी या आपूर्ति में बाधा उत्पन्न न हो।

डीआईजी ने ली जनरल परेड की सलामी टर्न आउट और अनुशासन की समीक्षा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

रक्षित केंद्र अंबिकापुर में शुक्रवार को आयोजित जनरल परेड की सलामी डीआईजी राजेश कुमार अग्रवाल ने ली। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण करते हुए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुशासन तथा टर्न आउट की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कृत भी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस बल की फिटनेस और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से नियमित रूप से जनरल परेड का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद डीआईजी-एसएसपी ने रक्षित केंद्र के शस्त्रागार और स्टोर

शाखा का निरीक्षण किया। उन्होंने हथियारों के सुरक्षित रखरखाव और रिकॉर्ड को अद्यतन रखने के निर्देश दिए। साथ ही उपकरणों की समय-समय पर मरम्मत कराने और उन्हें व्यवस्थित रखने की बात कही। वाहन शाखा के निरीक्षण के दौरान शासकीय वाहनों की स्थिति, रखरखाव और लॉग बुक की भी जांच की गई। अधिकारियों ने वाहन शाखा प्रभारी को सभी वाहनों को अच्छी स्थिति में रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लों,डीएसपी अमृत कुजूर, डीएसपी राकेश बघेल,डीएसपी सुरेश भगत, एसडीओपी ग्रामीण तूल सिंह पट्टावी,रक्षित निरीक्षक तृप्ति सिंह राजपूत सहित 174 अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

सर्वर ठप्प,डिलिवरी अटकी,गैस के लिए एजेंसियों पर उमड़ी भीड़

एक सप्ताह से सिलेंडर वितरण प्रभावित,शादी-विवाह के सीजन में बढ़ी चिंता;लकड़ी और कोयले की ओर लौट रहे लोग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

शहर में इन दिनों रसोई गैस को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। गैस एजेंसियों में सर्वर की समस्या और वितरण व्यवस्था प्रभावित होने के कारण लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। हालात यह हैं कि सुबह से ही एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही हैं और कई लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। शहर की एक प्रमुख गैस एजेंसी के बाहर बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर लेने पहुंचे। एजेंसी खुलने से पहले ही उपभोक्ता लाइन में लग गए थे। चिलचिलाती धूप में लोग दोपहर तक अपनी बारी का इंतजार करते रहे,लेकिन कई लोगों को गैस नहीं मिल सकी। उपभोक्ताओं का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से गैस की डिलिवरी व्यवस्था प्रभावित है। कई लोगों ने फरवरी के अंतिम दिनों में ऑनलाइन बुकिंग कराई थी,लेकिन अब तक उनके घरों तक

सिलेंडर नहीं पहुंच पाया है। इससे घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहे हैं और लोगों की चिंता बढ़ गई है। इधर गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि मुख्य समस्या सर्वर डाउन होने की है। सर्वर सही ढंग से काम नहीं कर रहा, जिससे बुकिंग की पर्ची नहीं कट पा रही है और वितरण प्रक्रिया बाधित हो रही है। एजेंसी संचालकों के अनुसार पहले जहां प्रतिदिन 300 से 400 बुकिंग आसानी से हो जाती थी,वहीं पिछले तीन-चार दिनों से मुश्किल से 10 से 12 बुकिंग ही दर्ज हो पा रही हैं। इस स्थिति के कारण एजेंसियों में भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग सुबह से ही सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं,जिससे अव्यवस्था की स्थिति बन रही है। वहीं जिला प्रशासन ने गैस की कमी की खबरों को अफवाह बताया है, लेकिन उपभोक्ताओं का कहना है कि वास्तविक स्थिति एजेंसियों के बाहर लगी कतारों से साफ दिखाई दे रही है।

शादी-विवाह के सीजन में बढ़ी चिंता : शहर में इन दिनों शादी-विवाह का सीजन चल रहा है। ऐसे में गैस की कमी ने कई परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। जिन घरों में शादी या अन्य आयोजन हैं,वहां लोग तैयारियों के साथ-साथ गैस की व्यवस्था को लेकर परेशान हैं। कई लोग घरेलू कामकाज छोड़कर एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ स्थानों पर कैटरिंग से जुड़े लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समय पर सिलेंडर नहीं मिलने से आयोजन की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। गैस सिलेंडर की किल्लत के चलते बाजार में लकड़ी और कोयले की मांग भी बढ़ने लगी है।

कई लोग वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इनका उपयोग करने लगे हैं। होटल और ढाबा संचालक भी एहतियात के तौर पर लकड़ी, कोयले और डीजल से चलने वाले चूल्हों की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि कामकाज प्रभावित न हो। गैस एजेंसियों का कहना है कि सर्वर की समस्या के कारण होम डिलिवरी भी प्रभावित हो गई है। कई बुकिंग दर्ज नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण सिलेंडर की डिलिवरी में देरी हो रही है। ऐसे में कई उपभोक्ताओं को खुद एजेंसी पहुंचकर गैस लेने की कोशिश करनी पड़ रही है।

राजाकटेल में पण्डो जनजाति की जमीन पर कब्जे के आरोप,कांग्रेस के जांच दल ने किया दौरा

दस्तावेज व सीमांकन नहीं होने से बढ़ा विवाद,रिपोर्ट के बाद कलेक्टर से मिलकर कैम्प लगाने की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

लखनपुर क्षेत्र के ग्राम राजाकटेल में विशेष संरक्षित पण्डो जनजाति की कृषि भूमि पर कथित कब्जे के मामले को लेकर शुक्रवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के निर्देश पर गठित 8 सदस्यीय जांच दल ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जांच दल का नेतृत्व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह ने किया। जानकारी के अनुसार, गांव में पण्डो जनजाति की कृषि भूमि पर बाहरी लोगों द्वारा कब्जा कर उन्हें बेदखल किए जाने की शिकायत सामने आई थी। इसके बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर जिला कांग्रेस ने एक जांच दल गठित कर मौके पर स्थिति की जानकारी ली। जांच दल में शामिल कांग्रेस महामंत्री एवं अधिवक्ता हेमंत तिवारी ने बताया कि वर्ष 1980 के दशक में सिंहदेव योजना के तहत गांव के पण्डो जनजाति के लोगों को भू-

अधिकार दिए गए थे,लेकिन आज तक उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। गांव में भूमि का न तो सीमांकन हुआ है और न ही कब्जे से संबंधित नक्शों का निर्धारण किया गया है। इसके कारण जमीन के मालिकाना हक को लेकर स्पष्टता नहीं है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार पण्डो जनजाति की जमीन के साथ-साथ गांव की कुछ शासकीय भूमि पर भी कब्जा किया गया है। विवाद सामने आने के बाद प्रशासन द्वारा गठित जांच दल ने भी अब तक मौके पर न तो नापजोख कराई और न ही सीमांकन की कार्रवाई की है। जांच दल की अध्यक्ष मधु सिंह ने बताया कि प्रभावित पण्डो जनजाति के लोगों ने चर्चा के दौरान अपनी समस्याएं बताई हैं। उनका कहना है कि मामले को साम्प्रदायिक रंग देकर राजनीति की जा रही है, जबकि जनजाति को राहत दिलाने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पण्डो समाज के लोगों ने न्याय की उम्मीद में कांग्रेस से संपर्क किया है। जांच दल दो दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जिला कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगा। जांच दल में लखनपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सिंहदेव, उदयपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रशांत सिंह, जिला पंचायत सदस्य मोनिका पैकरा, पूर्व महिला जिलाध्यक्ष संध्या रवानी तथा जगरोपन यादव भी शामिल रहे।

कैम्प लगाकर नापजोख की मांग : जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि अति संरक्षित पण्डो जनजाति की जमीन और शासकीय भूमि पर कब्जे का मामला गंभीर है। दोषियों की पहचान कर उन्हें हटाया जाना चाहिए और प्रभावित परिवारों को उनकी जमीन का अधिकार दिलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सरगुजा कलेक्टर से मिलकर ग्राम राजाकटेल में कैम्प लगाकर जमीन की नापजोख और सीमांकन कराने की मांग करेगा। यदि प्रशासन इस दिशा में कार्रवाई नहीं करता है तो कांग्रेस आंदोलन करने को बाध्य होगी।

विश्व ग्लॉकोमा सप्ताह : 40 वर्ष से अधिक उम्र के 3311 लोगों की हुई आंखों की जांच

मेडिकल कॉलेज सहित स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क शिविर,84 मोतियाबिंद मरीजों का सफल ऑपरेशन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

जिले में 8 से 14 मार्च तक विश्व ग्लॉकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष कार्यक्रम का थीम 'ग्लॉकोमा मुक्त विश्व के लिए एकजुट होना' रखा गया है। इसके तहत जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तथा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को इस गंभीर आंखों की बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शिविरों में 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की विशेष रूप से जांच की जा रही है। दृष्टिदोष से पीड़ित मरीजों को चश्मे भी वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही पहले से चिन्हित प्रेसबायोपिक मरीजों को भी चश्मा दिया जा रहा है। नेत्र सहायक अधिकारियों द्वारा इस आयु वर्ग के मरीजों की आंखों के दबाव की जांच कर ग्लॉकोमा की पहचान की जा रही है। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के ओपीडी में आने वाले 40 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक मरीज की आंखों के दबाव और रेटिना की जांच की जा रही है। विशेषज्ञों ने बताया कि ग्लॉकोमा, जिसे सामान्य भाषा में काला मोतिया या कांचियाबिंद भी कहा जाता है,आंखों की गंभीर बीमारी है। समय पर उपचार नहीं मिलने पर यह आंखों की रोशनी भी छीन सकती है।

डॉक्टरों के अनुसार आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के अधिक उपयोग से आंखों पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। आंखों की समस्याओं को नजरअंदाज करना धीरे-धीरे ग्लॉकोमा जैसी बीमारी का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों ने बताया कि ग्लॉकोमा कई बार उम्र बढ़ने के साथ या अनुवांशिक कारणों से भी हो सकता है। छोटे बच्चों में भी जन्मजात ग्लॉकोमा पाया जाता है। इसके अलावा आंख में चोट लगने से भी यह बीमारी हो सकती है। यदि शुरुआती अवस्था में बीमारी का पता चल जाए तो उपचार से इसे बढ़ने से रोका जा सकता है।

3311 लोगों की जांच,84 का ऑपरेशन : 8 से 13 मार्च के बीच आयोजित शिविरों में 40 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 3311 लोगों की आंखों की जांच की गई। इनमें 172 मरीज मोतियाबिंद के संभावित पाए गए, जबकि 17 मरीजों में ग्लॉकोमा के लक्षण मिले। इसके अलावा 314 प्रेसबायोपिक तथा 434 अन्य आंखों की बीमारियों से पीड़ित मरीज भी चिन्हित किए गए। विकासखंडों से रेफर किए गए 84 मोतियाबिंद मरीजों का मेडिकल कॉलेज में डॉ. रजत टोप्पो और डॉ. संतोष एक्का द्वारा सफल ऑपरेशन कर उनकी आंखों की रोशनी बहाल की गई।

समय पर जांच जरूरी : नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ. रजत टोप्पो ने बताया कि ग्लॉकोमा का प्रारंभिक इलाज आंखों में दवा डालकर किया जाता है। यदि बीमारी अधिक बढ़ जाती है तो इलाज जटिल और महंगा हो सकता है, जिसमें सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि हर वर्ष अपनी आंखों की जांच नेत्र रोग विशेषज्ञ या नेत्र सहायक अधिकारी से जरूर कराएं। बच्चों को भी कम रोशनी में पढ़ाई नहीं करने देना चाहिए, ताकि आंखों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। कार्यक्रम के समापन अवसर पर शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में विभागाध्यक्ष डॉ. संतोष एक्का और डॉ. रजत टोप्पो ने वार्ड में भर्ती मोतियाबिंद मरीजों और विभागीय स्टाफ को ग्लॉकोमा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पूरे सप्ताह चले कार्यक्रम में जिले के नेत्र सहायक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अंबिकापुर जनपद पंचायत में दिव्यांग सहायता एवं पंजीकरण शिविर संपन्न, 113 हितग्राहियों ने कराया पंजीकरण

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

समाज कल्याण विभाग, सरगुजा के तत्वावधान में आज जनपद पंचायत अंबिकापुर परिसर में दिव्यांगजनों के लिए विशेष सहायता एवं पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना तथा उन्हें आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराना था। शिविर के दौरान कुल 113 दिव्यांगजनों ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यू.डी. आई.डी.) कार्ड के लिए अपना पंजीकरण कराया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र हितग्राहियों को आवेदन फार्म भी उपलब्ध कराए गए। शिविर में ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें ट्राइसाइकिल,व्हीलचेयर,श्रवण यंत्र सहित अन्य सहायक उपकरणों की आवश्यकता है,उनका स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम द्वारा परीक्षण किया गया।

ग्राम सुरक्षा मजबूत करने को पुलिस ने किया कोटवार सम्मेलन

अवैध गतिविधियों और साइबर अपराध की सूचना तुरंत देने के निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

गांवों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और सूचना तंत्र को सक्रिय करने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में कोटवार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देश पर थाना दरिमा, चौकी रघुनाथपुर,चौकी केदमा तथा थाना उदयपुर क्षेत्र में कोटवारों की बैठक आयोजित की गई। सम्मेलन में ग्राम स्तर पर होने वाली आपराधिक गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान थाना प्रभारियों ने

कोटवारों से गांव की सुरक्षा व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों और संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में जानकारी ली। साथ ही गांव में होने वाले विवाद, झगड़े, दुर्घटना या जमीन संबंधी विवाद की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए कहा गया। सम्मेलन में साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोटवारों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और बैंकिंग धोखाधड़ी से लोगों को सतर्क करने की भी सलाह दी गई। बैठक में थाना प्रभारी दरिमा निरीक्षक राजेश खलखो, थाना प्रभारी उदयपुर निरीक्षक शिशिरकांत सिंह, चौकी प्रभारी रघुनाथपुर उप निरीक्षक आर.एन. पटेल सहित पुलिस अधिकारी और ग्राम कोटवार उपस्थित रहे।

100 किमी की यात्रा के बाद 200 मीटर में टोल की चोट! विधानसभा में गूंज सकता है मामला

स्टेट हाईवे पर सफर,लेकिन टोल नेशनल हाईवे का...चोटिया टोल की वसूली पर बवाल

- कुछ मीटर चले,पूरा टोल चुकाया ! कोरिया-एमसीबी के यात्रियों पर 'चोटिया टोल' का बोझ
- स्टेट हाईवे से आए,नेशनल हाईवे छुआ और टोल कट गया! चोटिया टोल पर नाराजगी
- कोरिया-एमसीबी के यात्रियों पर टोल का तर्कहीन बोझ? चोटिया टोल व्यवस्था पर बहस
- सफर अलग,टैक्स अलग ! चोटिया टोल की वसूली पर विधानसभा में उठेगा सवाल

-रवि सिंह-

कोरिया,13 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया और एमसीबी जिले के लोगों के लिए बिलासपुर और रायपुर की यात्रा लंबे समय से एक अजीब स्थिति का सामना कर रही है,यात्रियों का आरोप है कि वे अधिकांश दूरी स्टेट हाईवे पर तय करते हैं, लेकिन जैसे ही चोटिया के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-130 पर चढ़ते हैं,उन्हें पूरा टोल टैक्स देना पड़ता है, इस व्यवस्था को लेकर क्षेत्र के लोगों में लंबे समय से नाराजगी बनी हुई है, अब इस मुद्दे को विधानसभा तक ले जाने की तैयारी की जा रही है,जानकारी के अनुसार बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े ने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए सवाल तैयार कर विधानसभा में जमा किया है और संभावना है कि आगामी सत्र में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है।

लंबा सफर स्टेट हाईवे पर, टोल नेशनल हाईवे का

कोरिया और एमसीबी जिले से बिलासपुर या रायपुर जाने वाले अधिकतर वाहन खड़गवां मार्ग से स्टेट हाईवे का उपयोग करते हैं,इस मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों को लगभग 200 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी स्टेट हाईवे पर तय करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही वाहन चोटिया के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-130 पर प्रवेश करते हैं, वहां स्थित टोल प्लाजा पर तुरंत टोल वसूली शुरू हो जाती है, यात्रियों का कहना है कि कई बार उन्होंने नेशनल हाईवे पर मुश्किल से 100-200 मीटर ही दूरी तय की होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पूरा टोल देना पड़ता है।

लोगों का सवाल: बिना सड़क पर चले टोल क्यों?-इस व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों और वाहन चालकों के मन में एक बड़ा सवाल है जब पूरी यात्रा स्टेट हाईवे पर हुई है और नेशनल हाईवे पर मुश्किल से कुछ मीटर ही चले हैं, तो फिर पूरा टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? लोगों का कहना है कि टोल टैक्स का मूल उद्देश्य सड़क के रखरखाव और उपयोग के बदले शुल्क लेना होता है, लेकिन इस मामले में यात्रियों को उस सड़क का पूरा उपयोग किए बिना ही टोल देना पड़ रहा है।

रोजाना सैकड़ों वाहन प्रभावित

स्थानीय व्यापारियों और वाहन चालकों के अनुसार इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। इनमें शामिल हैं निजी वाहन, बसें, टैक्सी और यात्री वाहन, छोटे व्यापारिक वाहन, हर दिन इन वाहनों से टोल वसूला जाता है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है, व्यापारियों का कहना है कि इससे यात्रा की लागत बढ़ जाती है और आम लोगों की जेब पर भी असर पड़ता है।

वर्षों से उठ रही है मांग...

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है। कई वर्षों से इस मुद्दे को लेकर चर्चा होती रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है, लोगों की मांग है कि सरकार को इस व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या इस मार्ग से आने वाले वाहनों के लिए कोई राहत दी जा सकती है।

विधानसभा में उठ सकता है मुद्दा

अब इस मामले को लेकर उम्मीदें विधानसभा सत्र से जुड़ गई हैं, सूत्रों के अनुसार बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए सवाल तैयार कर विधानसभा में दिया है, यदि उन्हें सदन में बोलने का अवसर मिलता है तो वे सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कर सकते हैं।

क्या हो सकती है मांग...

- क्या स्टेट हाईवे से आने वाले वाहनों को टोल में राहत दी जा सकती है?
- क्या चोटिया टोल प्लाजा की व्यवस्था की समीक्षा की जा सकती है?
- क्या स्थानीय यात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था बनाई जा सकती है?

स्थानीय लोगों की अपेक्षा...

कोरिया और एमसीबी जिले के लोगों का कहना है कि यदि इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा होती है तो इससे हजारों यात्रियों को राहत मिल सकती है, लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस समस्या को समझेगी और कोई ऐसा समाधान निकालेगी जिससे यात्रियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।

अब निगाहें विधानसभा सत्र पर...

फिलहाल इस मुद्दे को लेकर लोगों की नजरें आगामी विधानसभा सत्र पर टिकी हैं, यदि यह मुद्दा सदन में उठता है और इस पर चर्चा होती है तो संभव है कि चोटिया टोल प्लाजा से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव की दिशा में कोई कदम उठाया जाए, लेकिन अगर यह मामला भी अन्य मुद्दों की तरह चर्चा से बाहर रह गया तो कोरिया और एमसीबी जिले के लोगों को शायद आगे भी इसी तरह कुछ मीटर सड़क पर चलने के बावजूद पूरा टोल देने की स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान संगठन मजबूती पर हुआ मंथन

-संवाददाता-
एमसीबी/जनकपुर,13 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जनकपुर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोटाडोल के नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान में जनकपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गुलाब कमरो एवं विशिष्ट अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी एमसीबी के उपाध्यक्ष रवि प्रताप सिंह की उपस्थिति में नव नियुक्त पदाधिकारियों का पुष्पमाला और गमछा पहनाकर सम्मान किया गया, कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संगठन की मजबूती और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने को लेकर विस्तार से चर्चा की। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनहित और सामाजिक न्याय की विचारधारा पर कार्य करती आई है। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सक्रिय और समर्पित रहना बेहद जरूरी है, उन्होंने उम्मीद जताई कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को गांव-गांव तक पहुंचाने के साथ ही आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास करेंगे, कार्यक्रम के दौरान पार्टी के दिशा-निर्देशों, संगठनात्मक नीतियों और पदाधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के अनुरूप कार्य करते हुए संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने का काम करें,इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जनकपुर के अध्यक्ष अंकुर प्रताप सिंह,ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोटाडोल के अध्यक्ष रामू सिंह,जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस उपेंद्र द्विवेदी सहित कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला।

छत्तीसगढ़ के शिमला मैनपाट में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल बनाएगा सर्वसुविधायुक्त पर्यटन-आवासीय परिसर

मैनपाट में 4.80 हेक्टेयर भूमि आवंटित, पर्यटन को मिलेगा नया आयाम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के 'शिमला' नाम से प्रसिद्ध मैनपाट में पर्यटन सुविधाओं और आवासीय विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य सरकार द्वारा मैनपाट में 4.80 हेक्टर (12 एकड़) भूमि अटल विहार योजना हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आवंटित की गई है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया कि इस भूमि पर आधुनिक एवं बहुउपयोगी पर्यटनदृआवासीय परिसर का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप विकसित होने वाली यह परियोजना मैनपाट आने वाले पर्यटकों को बेहतर, सुरक्षित और किफायती ठहराव उपलब्ध कराएगी। श्री सिंह देव ने कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी और पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के सक्रिय प्रयासों से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि मैनपाट में लगातार बढ़ते पर्यटक आगमन को देखते हुए इस तरह की सुविधाओं की

आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। प्रस्तावित परिसर में आधुनिक वेलनेस एवं मनोरंजन सुविधाएँ विकसित की जाएंगी। श्री सिंह देव ने बताया कि परियोजना में केरल मॉडल पर आधारित वेलनेस सेंटर, प्राकृतिक पंचकर्म चिकित्सा, हर्बल स्पा और आयुष सेवाएं प्रस्तावित हैं। साथ ही 24म7 क्लब हाउस, मिलेट्स कैफे, जिम, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, स्टीम बाथ और एंटरटेनमेंट ज़ोन विकसित किए जाएंगे। पर्यावरण अनुकूल विकास के तहत ट्री हाउस, कॉटेज और स्थानीय जीवन एवं संस्कृति का अनुभव कराने वाला सांस्कृतिक क्षेत्र भी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि परियोजना से मैनपाट में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होंगे और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नई संभावनाएं खुलेंगी। गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधा उपलब्ध होने से पर्यटकों का ठहराव समय बढ़ेगा, जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मैनपाट छत्तीसगढ़ का विशिष्ट एवं उभरता हुआ पर्यटन गंतव्य है। तेजी से बढ़ रही पर्यटक संख्या को देखते हुए यहाँ आधुनिक सुविधाओं का विकास अत्यावश्यक है। हाउसिंग बोर्ड की यह पहल पर्यटन,आवास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी तथा मैनपाट को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर सशक्त रूप से स्थापित करेगी। पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने परियोजना को छत्तीसगढ़ के पर्यटन विस्तार के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के विकास से पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और राज्य का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मजबूत होगा। सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोप्पो ने इसे मैनपाट के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह परियोजना स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं व्यापार के अवसर उपलब्ध कराएगी और क्षेत्र की पहचान को नई ऊँचाई देगी। अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि यह पहल छत्तीसगढ़ में पर्यटनदृआवास विकास के क्षेत्र में गृह निर्माण मंडल की ऐतिहासिक भूमिका को मजबूत करेगी और भविष्य में मैनपाट को एक प्रमुख राष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने का आधार बनेगी।

देवगढ़ में उप तहसील की घोषणा, उदयपुर क्षेत्र को मिली बड़ी प्रशासनिक सौगात

मंत्री राजेश अग्रवाल की मांग पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने विधानसभा में की घोषणा,अब ग्रामीणों को राजस्व कार्यों के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज सरगुजा जिले के उदयपुर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने विधानसभा में देवगढ़ में उप तहसील स्थापित किए जाने की घोषणा की। यह निर्णय उदयपुर क्षेत्र सहित देवगढ़ और आसपास के ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत और उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि लंबे समय से उदयपुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों द्वारा देवगढ़ में उप तहसील की स्थापना की मांग उठाई जा रही थी। अब इस मांग के पूरा होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को राजस्व और प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर-दराज के कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पडेगा। देवगढ़ में उप तहसील बनने से क्षेत्र के ग्रामीणों को नामांतरण,सीमांकन,आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र,भू-अभिलेख संबंधी कार्यों सहित अन्य राजस्व सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी। इससे न केवल आम लोगों का समय और खर्च बचेगा, बल्कि प्रशासनिक कामकाज भी अधिक सुगम और प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेगा। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे उदयपुर क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और ग्रामीणों को शासन की सेवाओं का लाभ और अधिक सहजता से प्राप्त हो सकेगा। देवगढ़ में उप तहसील की स्थापना को उदयपुर क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे क्षेत्र में प्रशासनिक पहुंच बढ़ेगी और विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी।

मेंड्राकला ग्राम पंचायत में विद्यार्थियों का अनुभवात्मक भ्रमण,स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों से हुए रूबरू

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

ग्रामीण विकास और पंचायत व्यवस्था की जमीनी समझ विकसित करने के उद्देश्य से राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर तथा मुहिम फाउंडेशन द्वारा जिला पंचायत सरगुजा के सहयोग से विद्यार्थियों का एक दिवसीय अनुभवात्मक अध्ययन भ्रमण आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को विकासखंड अंबिकापुर के ग्राम पंचायत मेंड्राकला का भ्रमण कराया गया, जहां उन्होंने पंचायत की विभिन्न स्थानीय संस्थाओं और गतिविधियों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने पंचायत स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनके कार्यों को समझा। इस अवसर पर विद्यार्थियों को पंचायत प्रतिनिधियों से सीधे संवाद का अवसर भी मिला,

जिससे उन्हें ग्रामीण प्रशासन और विकास कार्यों की प्रक्रिया को नजदीक से जानने का मौका मिला। कार्यक्रम का सबसे प्रेरणादायक और यादगार अनुभव विद्यार्थियों के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ संवाद रहा। समूह की महिलाओं ने बताया कि किस प्रकार स्वयं सहायता समूह केवल बचत और ऋण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के लिए सुरक्षा, सहयोग, आत्मविश्वास और सामूहिक शक्ति का मजबूत माध्यम बन चुका है। इस दौरान एक समूह सदस्य ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनके लिए सशक्तिकरण का अर्थ जागरूक होना, अपनी सोच रखना, अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ रखना और अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता विकसित करना है। उनके अनुभवों ने विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में नेतृत्व और सामुदायिक विकास की प्रेरणा प्रदान की। इस अनुभवात्मक भ्रमण के माध्यम से विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर समुदाय के बीच सीखने और समझने का अवसर मिला, जहां उन्होंने ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक नेतृत्व की वास्तविक कहानियों को करीब से जाना।

2 मामले मे वाहन चालको कों 20000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित

दोपहिया वाहन चालको द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही

-संवाददाता-
बतौली,13 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

सडक दुर्घटनाओ कों कम करने की दिशा मे डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान बजाज पल्सर मोटरसायकल क्रमांक सीजी/14/एम क्यू /7584 के चालक कुलदीप ठाकुर आत्मज कैलाश ठाकुर उम्र 20 वर्ष साकिन खड़धोवा थाना बतौली एवं वाहन क्रमांक सीजी/15/डी पी /7607 के चालक सुपील नागेश आत्मज धनसाय नागेश उम्र 34 वर्ष साकिन डहौली थाना लुन्ड्रा का होना बताया जो वाहन चालको का डॉक्टरी मुलाहिजा कराये जाने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया एवं नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालको के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अलग अलग प्रकरण दर्ज कर दोनों मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों प्रकरणों मे वाहन चालक कों 10000/- रुपये,10000/- के अलग अलग अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।

सूरजपुर में शाम ढलते ही सजता जुए का 'दरबार'

जंगल और सीमावर्ती इलाकों में बड़े जुआ खेल की चर्चा

सूरजपुर में जुए का बड़ा नेटवर्क? साइबर शाखा और थाना पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल

जंगल में 'कैसीनो', सिस्टम मौन ! सूरजपुर में शाम 4 से 8 बजे तक जुए का महाखेल

जुआ चलता रहा, कानून सोता रहा ! कुमेली जंगल बना सूरजपुर का नया 'कसीनो'

सूरजपुर का 'जंगल कैसीनो': शाम 4 से रात 8 तक जुए का मेला, सिस्टम की आंखों पर पट्टी?

कुमेली के जंगल और माजा गांव के आसपास सजती है कथित 'बुक',लाखों के दांव हार-जीत की चर्चा, साइबर और थाना पुलिस की भूमिका पर उठ रहे तीखे सवाल

शमशेर और एस कुमार के नाम चर्चा में, जंगल और सीमावर्ती इलाकों में चलने की बात – संरक्षण के आरोपों से पुलिसिंग पर घिरा सवाल

चार घंटे का जुआ शिफ्ट सिस्टम! शाम ढले लगती बुक,लाखों के दांव

जंगल में जुआ, शहर में खामोशी! संरक्षण की चर्चा से पुलिसिंग पर सवाल

कुमेली जंगल में 'जुआ दरबार'! हार-जीत लाखों में,कार्रवाई शून्य

जुए का नेटवर्क या सिस्टम की सेटिंग? सूरजपुर में रोज सजता 'शाम का खेल'

जंगल में बिछती ताश, शहर में बिछती चुप्पी! सूरजपुर का जुआ मॉडल चर्चा में

बुक खुलते ही लाखों का खेल! सूरजपुर में जुए के नेटवर्क पर उठे बड़े सवाल

-शमरोज खान-
सूरजपुर,13 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले में अवैध जुए के कथित बड़े नेटवर्क को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है, स्थानीय लोगों और मुखविरों के मुताबिक जिले में जुए का खेल कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी पुरानी परंपरा बनती जा रही है जिसे रोकने की कोशिशें हर बार कागजों में ही दम तोड़ देती हैं, फर्क बस इतना है कि अब यह खेल शहर की गलियों से निकलकर जंगलों और सीमावर्ती इलाकों की प्राकृतिक गोपनीयता में पहुंच गया है।

विशेष खोजी रिपोर्ट

चर्चा है कि कुमेली के जंगल और सूरजपुरङ्कोरिया सीमा के पास बसे माजा गांव के आसपास इन दिनों शाम होते ही कथित तौर पर जुए का मिनी महाकुंभ लगने लगता है,यहां चार घंटे तक ऐसा खेल चलता है,जिसमें लाखों रुपये के दांव लगने की बातें कही जा रही हैं, सबसे दिलचस्प बात यह बताई जा रही है कि यह खेल कथित तौर पर शाम 4 बजे से शुरू होकर रात लगभग 8 बजे तक चलता है,यानी सूरज ढलने से पहले ही जुए का बाजार सज जाता है और रात होने से पहले समेट भी लिया जाता है, मानो सब कुछ सिस्टम की सुविधा के हिसाब से तय किया गया हो।

अब देखना होगा....

सूरजपुर जिले में कथित जुए के इस नेटवर्क को लेकर उठे सवालों ने पुलिस व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है, अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं,क्या जंगल में लगने वाला यह जुआ दरबार बंद होगा, या फिर शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक यह खेल यूं ही चलता रहेगा, यह आने वाला समय ही बताएगा।

जंगल में जुआ, शहर में सन्नाटा

स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले जुए के कई ठिकाने शहर के आसपास सक्रिय रहते थे,समय-समय पर पुलिस कार्रवाई भी होती थी और खबरें भी सुर्खियां बनती थीं,लेकिन जैसे-जैसे निगरानी बढ़ी,वैसे-वैसे जुए के संचालकों ने भी अपनी रणनीति बदल ली, अब कथित तौर पर खेल शहर से दूर जंगलों और सीमावर्ती गांवों में पहुंच गया है,जंगल का फायदा यह कि वहां न तो ज्यादा आवाजाही होती है और न ही कोई आसानी से पहुंच पाता है,कुछ लोग व्यंग्य में कहते हैं कि शायद जुए के संचालकों ने वन्य पर्यटन की तर्ज पर नया मॉडल बना लिया है, जहां खिलाड़ी शहर से निकलकर जंगल पहुंचते हैं,खेल खेलते हैं और वापस लौट आते हैं,यह भी चर्चा है कि इन ठिकानों को चुनने के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि जंगल और सीमावर्ती इलाकों में पुलिस की नियमित गश्त कम रहती है।

शाम 4 से रात 8...चार घंटे का 'जुआ महोत्सव'

मुखविरों के अनुसार इस कथित जुए का समय भी बेहद अनुशासित है, खेल रोजाना लगभग एक ही समय पर शुरू होता है और तय समय पर खत्म भी हो जाता है, बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे के आसपास खिलाड़ी जुटने लगते हैं,उसके बाद बुक खुलती है और खेल शुरू होता है, धीरे-धीरे दांव बढ़ते जाते हैं और कई बार लाखों रुपये की हार-जीत सामने आती है, रात करीब 8 बजे तक पूरा खेल समेट लिया जाता है, कुछ लोग इसे मजाक में चार घंटे का जुआ शिफ्ट सिस्टम भी कह रहे हैं।

'बुक' में दर्ज होता है लाखों का हिसाब

सूत्रों का कहना है कि यहां केवल मौके पर बैठकर ताश खेलने तक ही मामला सीमित नहीं है,इसके साथ-साथ बुक भी लगती है, जिसमें हार-जीत का पूरा हिसाब दर्ज किया जाता है, बताया जा रहा है कि कई लोग सीधे मौके पर मौजूद रहते हैं,जबकि कुछ लोग बुक के माध्यम से दांव लगाते हैं, यही वजह है कि यहां कभी-कभी लाखों रुपये की हार-जीत की चर्चा सामने आती है,जुए के इस कथित नेटवर्क में आर्थिक लेन-देन का तरीका भी बेहद व्यवस्थित बताया जा रहा है,मानो कोई छोटा-मोटा कारोबार चल रहा हो।

कुछ नाम बार-बार चर्चा में...

स्थानीय चर्चाओं में इस पूरे कथित नेटवर्क से जुड़े कुछ नाम लगातार सामने आ रहे हैं, मुखविरों के अनुसार जुए के इस संचालन में शमशेर, एस कुमार,बबलू,विवेक,राजकुमार और संजू जैसे नामों की चर्चा होती रहती है, बताया जाता है कि इन लोगों के बीच जिम्मेदारियां भी बंटी हुई हैं,कोई खिलाड़ियों को जोड़ने का काम करता है, कोई बुक संभालता है और कोई पूरे संचालन की निगरानी करता है,हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है,लेकिन लगातार सामने आ रही चर्चाओं ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है।

कथित बंटवारे में कुछ पुलिसकर्मियों के नाम भी चर्चा में

सूत्रों के अनुसार इस कथित जुए के खेल में रोजाना लगभग 70 हजार रुपये अलग से निकाले जाने की चर्चा है,बताया जा रहा है कि इस रकम का एक हिस्सा अलग-अलग स्तरों पर बांटा जाता है, चर्चा यह भी है कि इसमें से करीब 30 हजार रुपये विभिन्न स्तरों पर खर्च होने की बातें कही जा रही हैं,मुखविरों के अनुसार कथित तौर पर कुछ नामों को पांच-पांच हजार रुपये और कुछ हिस्सा थाना स्तर तक पहुंचने की बातें भी सामने आ रही हैं, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है,मुखविरों के अनुसार इस पूरे कथित जुए के खेल में प्रतिदिन लगभग 70 हजार रुपये अलग से निकाले जाने की चर्चा है, बताया जा रहा है कि इस रकम का एक हिस्सा विभिन्न स्तरों पर खर्च होने की बात कही जा रही है, सूत्रों का दावा है कि इस कथित बंटवारे में कुछ पुलिसकर्मियों के नाम भी चर्चा में आ रहे हैं,बताया जाता है कि कथित रूप से विकास और महेंद्र नाम के दो पुलिसकर्मियों को लगभग 2500-2500 सौ रुपये मिलने की बात कही जा रही है,जबकि करीब 25 हजार रुपये रामानुजनगर थाना स्तर तक पहुंचने की चर्चा है,बाकि उदय और प्रभारी राजेश यादव के हिस्से में जाता है, हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है,लेकिन इस तरह की चर्चाओं ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है,स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इन दावों में सच्चाई है तो यह केवल जुए का मामला नहीं बल्कि पुलिस व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता से जुड़ा बड़ा सवाल बन सकता है।

रामानुजनगर थाना और साइबर शाखा पर सवाल

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सवाल रामानुजनगर थाना क्षेत्र और जिले की साइबर शाखा को लेकर उठ रहे हैं, लोगों का कहना है कि यदि रोजाना चार घंटे तक इतने बड़े स्तर पर जुए का खेल चलता है तो इसकी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं है,वहीं साइबर शाखा को लेकर भी व्यंग्य भरी चर्चाएं हो रही हैं,लोगों का कहना है कि साइबर सेल को तो अपराधों पर नजर रखने के लिए बनाया गया है,लेकिन यहां तो स्थिति उलटी दिखाई दे रही है,कुछ लोग तंज कसते हुए कहते हैं कि साइबर अपराध पकड़ने की जगह शायद साइबर अब जुए के नेटवर्क की निगरानी कर रहा है।

एस कुमार की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं

सूत्रों के अनुसार इस नेटवर्क में एस कुमार की भूमिका को लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यदि उन्हें अलग कर दिया जाए तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, यही कारण है कि नेटवर्क के भीतर उन्हें साथ लेकर चलने की रणनीति अपनाई जाती है, हालांकि यह सब चर्चाओं का हिस्सा है, लेकिन इन चर्चाओं ने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है।

बड़े अधिकारियों की चुप्पी पर भी सवाल

लगातार उठ रहे इन सवालों के बीच जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की चुप्पी भी चर्चा का विषय बन गई है, स्थानीय लोगों का कहना है कि जब इतने बड़े स्तर पर जुए के नेटवर्क की चर्चा हो रही है और खबरें भी सामने आ रही हैं, तो प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, कुछ लोग व्यंग्य में कहते हैं कि शायद जुए का यह नेटवर्क इतना अनुशासित है कि वह किसी को परेशान नहीं करता – इसलिए कार्रवाई की जरूरत ही नहीं समझी जा रही।

सिस्टम पर उठता बड़ा सवाल

पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि जंगलों और सीमावर्ती इलाकों में रोजाना जुए का इतना बड़ा खेल चल रहा है,तो आखिर इसे रोकने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है? या जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही? या फिर यह सब सिर्फ अफवाहें हैं? इन सवालों के जवाब अभी तक साफ नहीं हैं।

निष्पक्ष जांच की मांग

स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है, उनका कहना है कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो इसमें शामिल लोगों के साथ-साथ संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों का कहना है कि अवैध जुआ केवल कानून का उल्लंघन नहीं है,बल्कि इससे अपराध और सामाजिक समस्याएं भी बढ़ती हैं।

संगठन मजबूती की तैयारीः सूरजपुर कांग्रेस ने ब्लॉकवार प्रभारी किए नियुक्त

-संवाददाता-
सूरजपुर,13 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में जिला कांग्रेस कमेटी सूरजपुर ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह ने जिले के विभिन्न ब्लॉकों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। यह नियुक्तियां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार की गई हैं।

बताया गया है कि इन नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य जिले के सभी बूथों,पंचायतों और वार्डों में संगठनात्मक ढांचे को शीघ्र पूर्ण करना तथा कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है,इसके लिए प्रेमनगर, रामानुजनगर,सूरजपुर,प्रतापपुर, भैयाथान, सलका, लटोरी, ओड़गी और बिहारपुर ब्लॉकों में अलग-अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जारी आदेश के अनुसार प्रेमनगर ब्लॉक के लिए ईस्माईल खान और आनंद कुंवर को प्रभारी बनाया गया है, रामानुजनगर ब्लॉक में मेहदी यादव और बिहारी कुलदीप को को प्रभारी बनाया गया है, इसके अलावा लटोरी ब्लॉक के लिए इम्तियाज जफर और सुनील सारथी, ओड़गी ब्लॉक में अनिल गुप्ता और आशीष यादव तथा बिहारपुर ब्लॉक के लिए संजय यादव और अंशु पांडेय को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह ने सभी नियुक्त प्रभारीगण को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने प्रभार वाले ब्लॉकों में शीघ्र ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित करें, साथ ही संगठन विस्तार से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें, उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में संबंधित ब्लॉक अध्यक्षों के साथ पूर्व विधायक, वरिष्ठ कांग्रेसजन और पार्टी पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त और सक्रिय बनाया जा सके।

जिम्मेदारी दी गई है,सूरजपुर ग्रामीण ब्लॉक के लिए अशोक जगते और संजीव श्रीवास्तव को प्रभारी नियुक्त किया गया है,जबकि सूरजपुर शहर ब्लॉक की जिम्मेदारी नरेंद्र जैन और विकास सिंह को सौंपी गई है, इसी प्रकार प्रतापपुर ब्लॉक में सुनील अग्रवाल और अभिषेक श्रीवास्तव, भैयाथान ब्लॉक में संजय डोसी और प्रदीप साहू, तथा सलका ब्लॉक में नवीन जायसवाल और वेदप्रकाश मिश्रा

न्यायालय तहसीलदार अंबिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांकः, 202602020700190

विषयः-अ-27 मामले की श्रेणीः- राजस्व सनः-2025-26

भिटठीकला (प ह न. 00031), पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार - विश्वनाथ पिता देवनाथ विश्भर विनय कुमार, अनावेदक पक्षकार - विश्वनाथ पिता देवनाथ विश्भर विनय कुमार,

ईश्तहार

आवेदक विशम्भर आ0 देवनाथ व अन्य, निवासी ग्राम भिट्ठीकला, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम भिट्ठीकला स्थित खसरा नंबर 132/2, 133/2, 176, 177/2, 178/2 रकबा क्रमश 0.009, 0.113, 0.032, 0.025, 0.110 हे0 भूमि को उभयपक्ष के मध्य में 1/3 अंश में बटवारा किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 23.03.2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 17/02/2026 को जारी किया जाता है।

सील — उमेश्वर सिंह बाज तहसीलदार,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अंबिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांकः, 202602020700189

विषयः-अ-27 मामले की श्रेणीः- राजस्व सनः-2025-26

भिटठीकला (प ह न. 00031), पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार -बिसम्बर, विश्वनाथ, बिनयनाथ,बकनहीन, अनावेदक पक्षकार - बिसम्बर, विश्वनाथ, बिनयनाथ,बकनहीन,

ईश्तहार

आवेदक विशम्भर आ0 देवनाथ व अन्य, निवासी ग्राम भिट्ठीकला, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम भिट्ठीकला स्थित खसरा नंबर 20/1, 117/1,141/1, 156/1, 157/1, 213/1, 273/1, 273/134, 31, 333/1, 1279/1, 1301/2 कुल खसरा नंबर 11 कुल रकबा 4.529 हे0 भूमि को उभयपक्ष के मध्य में 1/3 अंश में बटवारा किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 23.03.2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 17/02/2026 को जारी किया जाता है।

सील — उमेश्वर सिंह बाज तहसीलदार,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा0प्र0क्र0-/ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुकुमार मतबर आ0 स्व0 दीपक मतबर व अन्य निवासी ग्राम सुभाषनगर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम सुभाषनगर स्थित खसरा नंबर 202/1 रकबा 0.780 हे0 भूमि में से 08 डिसमिल भूमि को अनावेदक सरिता साहू पति पन्नालाल साहू निवासी ग्राम सुभाषनगर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास अंकन राषि रूपये 14,15,000/- में बिक्री करने का सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एंव प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 25.03.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांकः- 02/03 /2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अम्बिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा0प्र0क्र0-/ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रेखा साना पति स्व0 कन्हाई लाल साना व अन्य निवासी ग्राम सुभाषनगर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम सुभाषनगर स्थित खसरा नंबर 264/3 रकबा 0.930 हे0 भूमि में से 30 डिसमिल भूमि को अनावेदक सुमित मिस्त्री आ0 खोकन मिस्त्री निवासी ग्राम सुभाषनगर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास अंकन राषि रुपये 30,00,000/- में बिक्री करने का सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एंव प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 25.03.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक-02/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अम्बिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा0प्र0क्र0-/ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रेमलता अग्रवाल पत्नी विनोद कुमार अग्रवाल निवासी भैयाथान रोड सूरजपुर जिला सूरजपुर छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की व्यपवर्तित भूमि ग्राम अम्बिकापुर स्थित खसरा नंबर 4551/11 रकबा 0.009 है0 भूमि एवं उसपर निर्मित मकान को अनावेदक संजय कुमार जागवानी आ0 उधादास नागवानी निवासी मायापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास बिक्री करने का सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एंव प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 25.03.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दान-आपत्ति पर कोई वि नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक-25/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अम्बिकापुर,सरगुजा

जिला न्यायालय बैकुंठपुर में गूंजा नारी सम्मान का संदेश, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं का हुआ सम्मान

न्यायालय परिसर में महिला शक्ति का सम्मान,अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रतिभाओं को मिला मंच

बैकुंठपुर जिला न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष आयोजन,उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का हुआ सम्मान

नारी सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश,जिला न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गरिमामय ढंग से मनाया गया

महिलाओं के योगदान को मिला सम्मान,बैकुंठपुर जिला न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भव्य कार्यक्रम

-संवाददाता-
कोरिया,13 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैकुंठपुर (जिला-कोरिया) के मार्गदर्शन में 8 मार्च 2026 को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बैकुंठपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भव्य एवं गरिमामय आयोजन किया गया, इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों,अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और महिलाओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया,कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के योगदान,उनके अधिकारों और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना था।

दीप प्रज्वलन के साथ हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ

कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माता के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया,इसके साथ ही कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई, उपस्थित अतिथियों एवं महिलाओं का स्वागत पारंपरिक तरीके से बैज और तिलक लगाकर किया गया,इस दौरान पूरे परिसर में उत्साह और सम्मान का वातावरण देखने को मिला।

मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे उपस्थित

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश पारिक उपस्थित रहे,उनके साथ जिला न्यायालय बैकुंठपुर में पदस्थ सभी न्यायिक अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए,इसके अलावा मनेंद्रगढ़,चिरमिरी और जनकपुर न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों की भी कार्यक्रम में उपस्थिति रही,कार्यक्रम में न्यायालय के कर्मचारी तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिला अधिवक्ताओं की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही,जिससे कार्यक्रम का महत्व और बढ़ गया।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समां

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस आयोजन में महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लिया,कार्यक्रम के दौरान कविता पाठ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गईं,जिनमें महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया,इन प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को जीवंत बना दिया और उपस्थित लोगों ने तालियों के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन किया।

उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का किया गया सम्मान

कार्यक्रम के दौरान जिला न्यायालय में कार्यरत महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्य और समर्पण के लिए प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, यह सम्मान महिलाओं के कार्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और मेहनत की सराहना के रूप में दिया गया,सम्मान प्राप्त करने वाली महिलाओं ने कहा कि यह सम्मान उन्हें अपने कार्य के प्रति और अधिक प्रेरित करेगा तथा वे भविष्य में भी पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती रहेंगी।

वक्ताओं ने महिलाओं की भूमिका पर डाला प्रकाश

कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा, प्रशासन, न्यायपालिका,चिकित्सा और सामाजिक कार्यों सहित सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपनी प्रतिभा और क्षमता का परिचय दे रही हैं,उन्होंने कहा कि महिलाओं के बिना समाज की प्रगति की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह महिलाओं का सम्मान करे और उन्हें समान अवसर प्रदान करे।

नारी सम्मान बनाए रखने का किया गया आह्वान

मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश पारिक ने अपने उद्बोधन में कहा कि महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी है,उन्होंने कहा कि नारी शक्ति समाज की आधारशिला है और महिलाओं के योगदान को सम्मान देना हम सभी का कर्तव्य है, उन्होंने सभी लोगों से यह आह्वान किया कि समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता की भावना को और अधिक मजबूत किया जाए तथा महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

महिला सशक्तिकरण का दिया गया संदेश

कार्यक्रम के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश दिया गया, इस आयोजन ने न केवल न्यायालय परिसर में कार्यरत महिलाओं को सम्मानित करने का अवसर प्रदान किया,बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की भावना को भी प्रोत्साहित किया,कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने महिलाओं के सम्मान,समान अधिकार और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस का होली मिलन समारोह

नेताओं व कार्यकर्ताओं ने दिया एकता और भाईचारे का संदेश

-संवाददाता-
मनेंद्रगढ़,13 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

रंगों के पावन पर्व होली के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ङ्कचिरमिरीङ्कभरतपुर के तत्वावधान में मनेंद्रगढ़ स्थित सर्कस ग्राउंड के पीछे भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कांग्रेस परिवार के पदाधिकारी,कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए और आपसी प्रेम, सौहार्द एवं भाईचारे के साथ होली का पर्व मनाया।

कार्यक्रम के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं,पूरे आयोजन में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला, उपस्थित सभी लोगों ने समाज में प्रेम, एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया, इस अवसर पर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली का पर्व प्रेम,सद्भाव और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। ऐसे आयोजन समाज और संगठन को मजबूत करने का कार्य करते हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार हमेशा समाज में एकता, सद्भाव और जनसेवा के संकल्प के साथ कार्य करता रहा है और आगे भी इसी भावना के साथ कार्य करता रहेगा,कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव,जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजेश साहू, वरिष्ठ कांग्रेसी रमेश सिंह,श्रीमती इंदिरा सेंगर, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रभा पटेल, जिला महामंत्री शरण सिंह, रफीक मेमन, पूनम सिंह, अनीत दुबे, ध्रुपद चौहान, व्यंकटेश सिंह, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ ग्रामीण अध्यक्ष रामनरेश पटेल, खड़गवां अध्यक्ष युधिष्ठिर कमरो, ब्लॉक कांग्रेस मनेंद्रगढ़ शहर अध्यक्ष सौरव मिश्रा सहित अन्य कई कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे, समारोह में सभी ने मिलकर रंगों के इस पावन पर्व का आनंद लिया और संगठन की मजबूती तथा समाज सेवा के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम का समापन आपसी भाईचारे और होली की शुभकामनाओं के साथ हुआ।

ममता बनर्जी का पुतला दहन: राष्ट्रपति के कथित अपमान के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन

एसटी मोर्चा के नेतृत्व में बैकुंठपुर के आदर्श चौक में विरोध प्रदर्शन,टीएमसी सरकार से मांगी माफी

-संवाददाता-
बैकुंठपुर,13 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

देश की राष्ट्रपति द्रौपती के कथित अपमान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने बैकुंठपुर में विरोध प्रदर्शन करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया, भाजपा एसटी मोर्चा के नेतृत्व में नगर पंचायत पटना के आदर्श चौक में आयोजित इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने टीएमसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नाराजगी जाहिर की और इस मामले में सार्वजनिक माफी की मांग की।

राष्ट्रपति का अपमान,आदिवासी समाज का भी अपमानःभाजपा

अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष विमलचंद चेरवा ने कहा कि देश की राष्ट्रपति के साथ हुआ कथित व्यवहार बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने कहा कि यह केवल देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान नहीं है,बल्कि इससे पूरे आदिवासी समाज की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है,उन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह की घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और इस मुद्दे पर देशभर में विरोध दर्ज कराया जा रहा है।

टीएमसी सरकार की मानसिकता उजागरः गायत्री सिंह

नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री सिंह ने कहा कि यह घटना टीएमसी सरकार की मानसिकता को दर्शाती है, उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रपति के सम्मान से जुड़ा यह मामला बेहद गंभीर है और इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, उन्होंने राज्य सरकार से इस पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब देने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की।

भारी संख्या में जुटे भाजपा कार्यकर्ता

विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे,प्रमुख रूप से भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह, जिला महामंत्री कपिल जायसवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री सिंह, नगर पंचायत उपाध्यक्ष गौरव अग्रवाल, जिला सह मीडिया प्रभारी वर्षा साहू, जिला सोशल मीडिया सह प्रभारी राकेश गुप्ता, भाजपा मंडल अध्यक्ष रामलखन यादव, महामंत्री सत्यम साहू, सच्चिदानंद द्विवेदी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष विमलचंद चेरवा, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष दिलराज रवि, अजजा मोर्चा जिला महामंत्री कमलेश एक्का, राय सिंह, जिला मंत्री विश्वनाथ सिंह, पार्षद राजेश सोनी, रेखा वर्मा, अहिबरन सिंह, अजजा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मंगल सिंह, जिला मंत्री रमेश पोया, देवेन्द्र कुमार सिरदार, आशीष सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे, प्रदर्शन के अंत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के सम्मान से जुड़े मुद्दे पर देशभर में आवाज उठाने और इस तरह की घटनाओं के खिलाफ लगातार विरोध जारी रखने की बात कही।

फार्मेसी-काउंसिल के रजिस्ट्रार की नियुक्ति रद्द

हाईकोर्ट ने माना,काउंसिल को है रजिस्ट्रार की नियुक्ति का अधिकार,राज्य-शासन का आदेश अवैध

बिलासपुर,13 मार्च 2026। हाईकोर्ट के जस्टिस पीपी साहू ने छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद पर की गई नियुक्ति को अवैध माना है। कोर्ट ने नियुक्ति को रद्द कर दिया है। साथ ही कहा कि काउंसिल के प्रस्ताव के बगैर हुई नियुक्ति को वैध नहीं माना जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने राज्य शासन को फार्मेसी एक्ट 1948 और 1978 के नियमों के अनुसार नई नियुक्ति की छूट दी है। दरअसल, रायपुर निवासी डॉ. राकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार के पद पर 14 मार्च 2024 को हुई नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। याचिका में बताया गया कि अश्वनी गुर्देकर को रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति दी गई है,जो नियमों के विरुद्ध है। इसलिए उनकी नियुक्ति निरस्त की जाए। इस मामले पर दिए गए फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 26 के अनुसार रजिस्ट्रार की नियुक्ति का अधिकार राज्य काउंसिल के पास है और राज्य सरकार की भूमिका केवल पूर्व स्वीकृति देने तक सीमित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कानून किसी कार्य को एक विशेष तरीके से करने का प्रावधान करता है तो उसे उसी तरीके से किया जाना अनिवार्य है। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि जिस आदेश से रजिस्ट्रार का प्रभार दिया गया,उसके लिए काउंसिल की ओर से कोई प्रस्ताव या निर्णय रिकॉर्ड पर नहीं था। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा सीधे आदेश जारी करना वैधानिक प्रक्रिया के विपरीत पाया गया।

नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की छूट

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे फार्मेसी एक्ट 1948 और 1978 के नियमों के अनुसार नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यानी कि हाईकोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल को रजिस्ट्रार की नियुक्ति करने की छूट दी है।

सदन में हंगामा...अनुदान मांगों की चर्चा में अफसर नदारद

भूपेश बोले...सभी विभाग में अफसरशाही जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट

रायपुर,13 मार्च 2026। विधानसभा बजट सत्र के दौरान अनुदान मांगों की चर्चा पर सदन में हंगामा हो गया। शुक्रवार को उच्च शिक्षा और राजस्व विभाग के अधिकारी सदन में चर्चा के समय अनुपस्थित रहे, जिससे विपक्ष ने नाराजगी जताई। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि अधिकारियों की सरकार के प्रति जवाबदेही खत्म हो गई है और मंत्री भी कभी-कभी चर्चा में देरी से आए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी विभागों में अफसरशाही व्याप्त है और अधिकारियों का जवाबदेही खत्म हो गई है। सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया, हंगामा और नारेबाजी के बीच विपक्ष ने अपनी नाराजगी व्यक्त की।

चंद्राकर बोले...दुग्ध उत्पादन में हम आत्मनिर्भर नहीं

विधानसभा बजट सत्र के प्रश्नकाल में गौवंश,कृत्रिम गर्भाधान,दुग्ध उत्पादन और मादा पशुओं की प्रजनन नीति जैसे अहम मुद्दों की गूंज रही है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने मादा गौवंशीय पशुओं की संख्या, गर्भाधान नीति और टीकाकरण व्यवस्था पर सवाल उठाए। चंद्राकर ने कहा, 'दुग्ध उत्पादन में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, इस क्षेत्र में स्थिति बहुत दयनीय है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार आपकी है, काम आप नहीं कर पा रहे और आरोप हम पर लगा रहे हैं। इसी दौरान

चिराग परियोजना और नए केंद्रों की स्थापना पर भी चर्चा हुई। विपक्षी नेता चरणदास महंत ने गांवों की बछिया और कृत्रिम गर्भाधान के मुद्दे को सामने रखा, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिराग परियोजना की राशि और कार्यप्रगति पर सवाल किए। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने योजनाओं की स्थिति, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जानकारी दी। सदन में 77 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगे,जिनमें कानून-व्यवस्था,किसानों और पशुपालकों से जुड़े सवाल शामिल थे।

विपक्ष के सवाल और पक्ष का जवाब

- **अजय चंद्राकर :** प्रदेश में मादा गौवंशीय पशुओं की संख्या कितनी है? 53 लाख मादा गौवंश के लिए गर्भाधान,पशु प्रजनन नीति और टीकाकरण की व्यवस्था कैसे की जा रही है?
- **रामविचार नेताम:** कृत्रिम गर्भाधान के लिए पूरे प्रदेश में उपकेंद्र और पशु औषधालय उपलब्ध हैं। बेहतर नस्ल विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि दुग्ध उत्पादन बढ़े और राष्ट्रीय औसत के बराबर लाया जा सके।
- **अजय चंद्राकर:** दुग्ध उत्पादन में हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं हैं? 1585 संस्थाएं सरकारी हैं या गैर-सरकारी? 412 नए केंद्र कब खोले जाएंगे?
- **रामविचार नेताम:** बछिया उत्पादन बढ़ाने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत काम हो रहा है, निजी क्षेत्र का सहयोग भी लिया जा रहा है।
- **अजय चंद्राकर:** एक साल में कितने पशुओं का गर्भाधान का लक्ष्य है और अब तक कितने पशुओं का गर्भाधान किया गया?
- **रामविचार नेताम:** इसकी विस्तृत जानकारी अलग से उपलब्ध कराई जाएगी।
- **अजय चंद्राकर:** 183 करोड़ रुपए की चिराग परियोजना समय से पहले क्यों बंद हुई? जिम्मेदार कौन है?
- **रामविचार नेताम:** पूर्व प्रगति अपेक्षित नहीं होने के कारण भारत सरकार ने समीक्षा कर नोटिस देकर परियोजना बंद कर दी।
- **अजय चंद्राकर:** परियोजना बंद होने के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं और उन पर क्या कार्रवाई होगी?
- **रामविचार नेताम:** परीक्षण कराया जाएगा और जवाबदेही तय कर आवश्यक अनुशंसा भेजी जाएगी।
- **चरणदास महंत:** क्या 53 लाख की संख्या में गांवों की बछिया भी शामिल हैं? उनके लिए क्या योजना है?

अनुदान मांगों पर सदन में बहस

- **सवाल:** दलेश्वर साहू पहाड़ी की जमीन को उपजाऊ जमीन बताकर पट्टा क्यों दे दिया गया और बाद में पट्टा धारी जमीन को रायपुर के व्यापारी को कैसे बेच दिया गया?
- **जवाब:** राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा (मंत्रि का जवाब इस समय उपलब्ध नहीं, सदन में मामले की जांच के बाद कार्रवाई होगी)
- **सवाल:** दलेश्वर साहू राजस्व विभाग से जुड़े हजारों मामले पेंडिंग क्यों पड़े हैं और समय पर समाधान क्यों नहीं होता?
- **जवाब:** राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा पटवारी और तहसीलदार का अमला समय पर समस्या निदान के लिए काम कर रहा है,लेकिन कुछ मामलों में प्रक्रिया लंबित रहती है। आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- **सवाल:** उमेश पटेल रायगढ़ में बीज वितरण के दौरान 85% किसानों के रकबे का बीज रिजेक्ट क्यों कर दिया गया? इसका कारण क्या रहा?
- **जवाब:** मंत्री रामविचार नेताम उन क्षेत्रों में बीज तो दिया गया, लेकिन किसानों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला था। इसलिए उत्पादन कम हुआ।
- **सवाल:** उमेश पटेल जब प्रशिक्षण नहीं दिया गया तो जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं और क्या कार्रवाई होगी?
- **जवाब:** रामविचार नेताम आगे सुनिश्चित करेंगे कि किसानों के माध्यम से बेहतर बीज उत्पादन हो। जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है, उनकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के 24 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 498.83 करोड़

किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर कार्यरत है डबल इंजन सरकार : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर,13 मार्च 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की राजधानी गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त जारी की। इस दौरान देशभर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में लगभग 18 हजार 640 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के 24 लाख 71 हजार किसानों के खातों में 498.83 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना राशि अंतरण एवं पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को हर वर्ष तीन किश्तों में कुल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो किसानों के परिश्रम और उनके योगदान के

सम्मान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 हजार 283 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार बनने के बाद सबसे पहले किसानों को बोनस राशि प्रदान की गई और 13 लाख किसानों के खातों में 3 हजार 716 करोड़ रुपये अंतरित किए गए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के 48 घंटे के भीतर किसानों के खातों में भुगतान सुनिश्चित किया गया। इसके साथ ही कृषक उन्नति योजना के तहत 25 लाख से अधिक किसानों के खातों में 10 हजार 324 करोड़ रुपये की राशि होली से पहले अंतरित की गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दलहन,तिलहन, मक्का,कोदो-कुटकी,रागी और कपास जैसी फसलों की खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सिंचाई के लिए कृषि पंपों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके लिए इस वर्ष के बजट में 5 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से दो वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना भी शुरू की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बड़ी मदद साबित हो रही है। उन्होंने किसानों से धान के साथ-साथ अन्य फसलों की खेती की ओर भी ध्यान देने की अपील की, जिससे पानी की बचत होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन के 17 दिन शेष

बैज ने पूछा-मार्च बाद नक्सली घटनाओं की जिम्मेदारी किसकी होगी

जगदलपुर,13 मार्च 2026। देश से नक्सलवाद खत्म करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तय की गई 31 मार्च 2026 की डेडलाइन को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जगदलपुर में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब इस तारीख के आने में महज 17 दिन ही बाकी हैं। ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि अगर इस डेडलाइन के बाद भी नक्सली घटनाएं होती हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बैज ने कहा कि बस्तर में लंबे समय से नक्सलवाद और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बीच आम आदिवासी भी प्रभावित होते रहे हैं। ऐसे में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि 31 मार्च के बाद सुरक्षा, न्याय और आदिवासियों के अधिकारों को लेकर क्या गारंटी दी जा सकती है?

बैज ने कहा कि नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर केवल समयसीमा घोषित करने से समस्या खत्म नहीं होती। सरकार को जमीन पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि डेडलाइन के बाद अगर घटनाएं जारी रहती हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी।

भाजपा महिला पार्षद ने जहर खाकर की आत्महत्या की कोशिश अस्पताल में नेताओं की लगी भीड़

रायगढ़,13 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में रायगढ़ नगर निगम की भाजपा महिला पार्षद ने आत्महत्या की कोशिश की है। नेहा देवांगन रायगढ़ नगर निगम में वार्ड क्रमांक 2 से भाजपा की पार्षद हैं। उन्होंने आज अपने घर में जहर खाकर जान देने की कोशिश की। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। भाजपा की महिला पार्षद नेहा देवांगन ने आज अपने घर में जहर खा लिया। जब उनके घर वालों को पता चला तो पड़ोसियों की मदद से पार्षद को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में महिला पार्षद का इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार महिला पार्षद की स्थिति अभी खतरे से बाहर है। अगले 24 घंटे तक डॉक्टरों ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है। वहीं महिला पार्षद ने किन कारणों से जहर खाया है इसका खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार कोई सुसाइड नोट भी महिला पार्षद के पास से नहीं मिला है। महिला के परिजनों ने आत्महत्या की कोशिश के संबंध में किसी भी किस्म की जानकारी देने से इनकार कर दिया है पर महिला पार्षद के घर में जहर खाने के चलते किसी घरेलू कारणों से जहर खाने की बात चर्चा में है। हालांकि पुलिस महिला पार्षद के सामान्य स्थिति में आने का इंतजार कर रही है,जिसके बाद उनका बयान लिया जाएगा। वहीं घटना के बाद शहर में खलबली मच गई। शहर की राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई। लोग इस घटना से अचंभित है और सभी इसका कारण जानना चाह रहे हैं। घटना की जानकारी लगते ही महापौर, नगर निगम के सभापति तथा अन्य पार्षदों ने भी अस्पताल पहुंचकर पार्षद के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। अब महिला पार्षद के होश में आने के बाद उनके बयान के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट होगी।

ईओडब्ल्यू-एसीबी ने बैंक घोटाले में चालान पेश किया,ढाई करोड़ गबन की जांच जारी

रायपुर,13 मार्च 2026। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो ने एसबीआई के मुख्य शाखा प्रबंधक विजय कुमार अहके के विरूद्ध विशेष न्यायालय में चालान पेश कर दिया है। ब्यूरो ने अहके की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच में बैंक का 'रखवाला' को ही 'लुटेरा' बताया है। ब्यूरो ने रायपुर द्वारा भारतीय स्टेट बैंक,स्पेशलाइज्ड करेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, बैरन बाजार, रायपुर में हुए गबन पर धारा 316(5), 318(4),338, 336 (6), 340 (2) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 13 (1) (ए) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत विशेष न्यायालय, रायपुर में 1,290 पेज का अभियोग पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किया है। आरोपी केन्द्रीय जेल, रायपुर में निरुद्ध हैं। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी विजय कुमार अहके ने मुख्य शाखा प्रबंधक के पद पर रहते हुए अपने पदीय अधिकार का दुरुपयोग करते हुए 28 अगस्त 24 से 11 जून 25 के मध्य कम्प्यूटर के माध्यम से कूटरचित Queue (वाउचर) तैयार कर SCAB शाखा के ब्रांच जनरल लेजर खाते से शासकीय लोक धन का गबन किया। अहके ने वैच मोड प्रक्रिया का उपयोग कर प्रत्येक लेनदेन की राशि 5,00,000 रुपये (पाँच लाख रुपये) से कम रखी, ताकि बैंक के हाई वैल्यू ट्रांसफर अलर्ट सिस्टम से बचा जा सके। साथ ही 30 दिन के भीतर क्लरु खाते की पुरानी प्रविष्टियों को रोलओवर कर नई प्रविष्टि में परिवर्तित किया जाता था, जिससे नियंत्रक अधिकारी को वास्तविक वित्तीय स्थिति की जानकारी न हो सके।

विजय ने गबन की समस्त राशि कुल 75 लेनदेन के माध्यम से अपनी धर्मपत्नी के बैंक खाते में स्थानांतरित की,जिसमें आरोपी ने अपना मोबाईल नंबर लिंक कर रखा था,जिससे समस्त ओटीपी स्वयं आरोपी को प्राप्त होते थे।

छत्तीसगढ़ में 3 साल में एससी-एसटी एक्ट के 2455 केस

1013 रेप,73 मर्डर,2269 मामलों में चालान पेश,पीड़ितों को 28 करोड़ की मदद

रायपुर, 13 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2026 तक एससी-एसटी एक्ट के तहत 2455 केस दर्ज हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या रेप के मामलों की है, जो कुल मामलों का करीब 41% यानी 1013 केस हैं। लगभग हर 3 मामलों में से एक केस रेप से जुड़ा है। इसके अलावा 73 मर्डर के मामले भी दर्ज किए गए हैं। वहीं, मारपीट कर चोट पहुंचाने के 380 मामले दर्ज हुए,गंभीर चोट पहुंचाने के 60 केस सामने आए। जबकि 30 मामलों में अपहरण की घटनाएं दर्ज की गईं। विधानसभा में सरकार ने बताया कि यह सभी आंकड़े राज्य के अलग-अलग जिलों से मिले रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े अपराधों के मामलों को लेकर सरकार ने विधानसभा में आंकड़े पेश किए हैं। यह जानकारी 12 मार्च को विधानसभा के लिखित प्रश्नोत्तर के दौरान सामने आई। इस डेटा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या सबसे ज्यादा बताई गई है। बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले ने सरकार से सवाल किया था कि, पिछले 3 साल में एससी-एसटी एक्ट के तहत कितने केस दर्ज हुए और उनमें किस तरह के अपराध शामिल हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि इन मामलों में से कितनों में पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया है।

राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर भाजपा मोर्चा ने किया प्रदर्शन

बिलासपुर में ममता बनर्जी का पुतला फूंका

बिलासपुर,13 मार्च 2026। बिलासपुर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन और उनके कथित अपमान के विरोध में किया गया। कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला भी फूंका।

मोर्चा के कार्यकर्ता दोपहर में भाजपा कार्यालय से जुलूस के रूप में निकले। उन्होंने पुराना बस स्टैंड स्थित श्यामाप्रसाद मुखर्जी चौक पर पहुंचकर ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उग्र प्रदर्शन किया।

अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्याम सिंह ध्रुव ने इस दौरान कहा कि देश की आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान अपमान निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मोर्चा इसकी कड़ी निंदा करता है और इसी अपमान के विरोध में ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया।

इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष लखन लाल पैकरा,जिला महामंत्री सचिन कायरवार,अमित टोप्पो,प्रकाश कायरवार,भारती परते,युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष वैभव गुप्ता,धीरेंद्र केशरवानी,जुगल अग्रवाल,पार्षद गणेश रजक,सनी केसरी,शैलेश मिश्रा, रीना गोस्वामी,संध्या चौधरी और रिंकू मित्रा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

गौधाम योजना शुभारंभ समारोह
एवं
पशुपालक सम्मेलन

14 मार्च 2026

दोपहर 2:00 बजे

गौधाम लाखासार एवं
गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय
प्रेक्षागार, बिलासपुर (छ.ग.)

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

वर्चुअल मोड में
राज्य के समस्त जिलों में शुभारंभ

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

निराश्रित, घुमन्तू तथा जब्त किए गए गौवंश का संरक्षण एवं संवर्धन

₹05 लाख
प्रति वर्ष अधोसंरचना निर्माण/मरम्मत के लिए

₹47 हजार-2.85 लाख
प्रति वर्ष (1-5 एकड़) चारा विकास के लिए

₹13,126
प्रति माह गौ सेवकों को मानदेय

₹10,916
प्रति माह चरवाहों को मानदेय

अनुदान

पोषण आहार

- प्रथम वर्ष ₹10 प्रतिदिन/पशु
- द्वितीय वर्ष ₹20 प्रतिदिन/पशु
- तृतीय वर्ष ₹30 प्रतिदिन/पशु
- चतुर्थ वर्ष ₹35 प्रतिदिन/पशु

संरक्षण भी, संवर्धन भी
गौवंश के लिए समर्पित
साय सरकार

संचालन हेतु पात्र संस्थाएं –

छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग में पंजीकृत संचालित गौशाला की समिति, स्वयंसेवी संस्था, एन.जी.ओ. (गैर-सरकारी संगठन), ट्रस्ट तथा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एवं सहकारी समिति

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

संवाद 47200/62

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)